वर्ष 12 • अंक 298 • 14 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

रविवार 2 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

डॉलर रु. 71.40 (बाजार बंद) |
यूरो रु. 78.70 (बाजार बंद) |
सोना (10ग्राम) रु 40628 (बाजार बंद) |
सेंसेक्स 39735.50 ▼ 899.00 |
निफ्टी 11661.80 ▼ 300.30 |
निफ्टी फ्यूचर्स 11654.90 ▼ 06.90 |
ब्रेंट क्रूड 56.30 डॉलर (बाजार बंद)

बजट 2020-21

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

राहुल गांधी, नेता, कांग्रेस

बजट में कोई रणनीतिक योजना नहीं, केवल बड़ी-बड़ी बातें हुईं

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

बजट से आर्थिक वृद्धि होगी तेज और सभी लोग होंगे लाभान्वित

राजकोषीय घाटा 3.8% वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.5 प्रतिशत

आयकर दर 10% 5 लाख रुपये और 7.5 लाख रुपये के बीच आय पर बिना किसी रियायत के कर की नई दर

विनिवेश लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रु सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बिक्री से 323 प्रतिशत इजाफे का लक्ष्य

मुश्किल हालात ने बांधे सरकार के हाथ

बजट की कवायद

वृद्धि का इरादा, व्यय में इजाफा

बजट में व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये बढ़ोतरी करने का मजबूत संकेत दिया गया है। वित्त वर्ष 2021 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 3.5 प्रतिशत तक रखा जाएगा

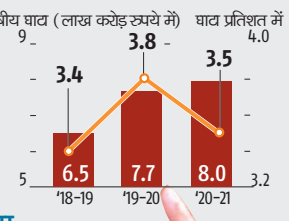

उपायों से मांग में वृद्धि की संभावना

उत्पादक परिसंपत्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव नहीं। नई आयकर दरों से मध्यम वर्ग के पास खर्च करने योग्य अधिक होगी रकम। कॉर्पोरेट कर में कटौती के साथ निवेश एवं मांग बढ़ाने में मिलेगी मदद

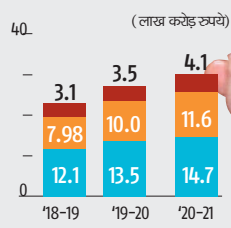

विनिवेश एवं गैर-कर राजस्व पर सारा दारोमदार

इसे हासिल करने के लिए आयकर में महत्त्वाकांक्षी वृद्धि की दरकार, सरकार नियंत्रित कंपनियों में हिस्सेदारी बिक्री और सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाले लाभांश से सरकार खजाने में रकम का होगा सतत प्रवाह

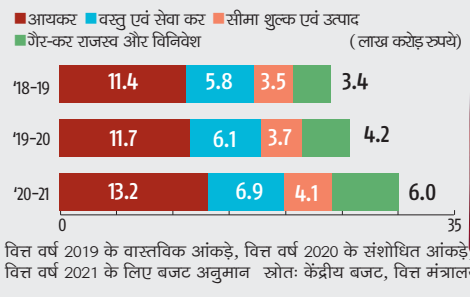

वित्त वर्ष 2019 के वास्तविक आंकड़े, वित्त वर्ष 2020 के संशोधित आंकड़े, वित्त वर्ष 2021 के लिए बजट अनुमान स्रोतः केंद्रीय बजट, वित्त मंत्रालय

समृद्धि के प्रतीक पीले रंग की साड़ी पहने शनिवार को संसद में बजट पेश करने जातीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

फोटो : संजय शर्मा

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 1 फरवरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश के इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, जो 2 घंटे 37 मिनट तक चला। इस मैराथन भाषण के दौरान उन्होंने बजट प्रक्रिया में भरोसा बहाल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए वह राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के दायरों में ही रहीं। सरकार के पास सीमित संसाधन होने की बात पहले ही कही जा रही थी और बजट भाषण ने उसे सही साबित कर दिया। सरकार ने खर्च में कंजूसी बरती और राहत-रियायत भी ऐसे पेचों के साथ दी गईं कि खजाने पर खास बोझ नहीं पड़ेगा।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.8 फीसदी तक पहुंचा दिया मगर अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी के 3.5 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है। कर राजस्व में कमी को देखते हुए घाटा बढ़ने का अंदेशा था, लेकिन राज्यों को धन देने और मध्य वर्ग को कर में राहत देने के बाद भी सीतारमण इसे साधन में कामयाब रहीं। चालू वित्त वर्ष में घाटा जीडीपी के 3.3 फीसदी पर ही समेटने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसमें 0.5 फीसदी बढ़ोतरी हो गई। लेकिन खास इजाफा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि खर्च के मामले में हाथ बांध लिया गया था और सार्वजनिक क्षेत्र तथा भारतीय रिजर्व बैंक से अच्छा खासा लाभांश भी मिल गया। उन्होंने पूंजीगत व्यय में 18 फीसदी इजाफा कर सरकार के संकल्प को दोहराया। मगर अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का सरकार का लक्ष्य हैरत में डालने वाला है। वित्त मंत्री ने 2020-21 में विनिवेश के जरिये 2.1 लाख करोड़ रुपये कमाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाकर भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी हिस्सेदारी भी बेचेगी।

बजट से इतर उधारी को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सीतारमण ने बजट से इतर संसाधनों का ब्योरा भी दिया। इन उधारियों – विशेषकर खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष से ली जाने वाली उधारी – को जोड़ें तो 2020-21 में वास्तविक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.5 फीसदी तक पहुंच सकता है।

बजट से पहले व्यक्तिगत आयकर पर कई तरह की चर्चा हो रही थीं। वित्त मंत्री ने मध्य वर्ग की चिंताएं खत्म करने के लिए आयकर घोषणापत्र लाने और कानून बनाने तथा करदाताओं को सरकार के साथ चल रहे कर विवाद केवल विवादित कर राशि देकर सुलझाने का मौका देने की घोषणा की। साथ ही बैंक खातों में 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपये तक जमा राशि के बीमा का ऐलान भी किया गया। लेकिन आयकर दरें घटाने के मामले में उन्होंने कुछ अलग किस्म का प्रस्ताव रखा। नए प्रस्ताव के तहत आयकर की दरों में कमी की गई है। इसके तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर पहले की ही तरह कर लगता रहेगा मगर 5 से 7.5 लाख रुपये तक आय पर 20 के बजाय 10 फीसदी और 7.5 लाख से 10 लाख रुपये तक 15 फीसदी कर देना होगा। इसी तरह 10 से 12.5 लाख रुपये तक 20 फीसदी और 12.5 से 15 लाख रुपये तक 25 फीसदी की दर से कर लगेगा। लेकिन इन दरों का फायदा लेने के लिए सभी प्रकार की कर रियायत और छूट छोड़नी होंगी, जिनमें आवास ऋण के ब्याज पर छूट और आवास किराया भत्ता में छूट आदि भी शामिल हैं। ये दरें वैकल्पिक हैं और जो करदाता छूट का फायदा लेना चाहते हैं, वे पुरानी दरों पर आयकर दे सकते हैं। जाहिर है कि नई दरें कर बचाने वाली योजनाओं में निवेश के युवा पीढ़ी के फैसलों में बदलाव ला देंगी।

वित्त मंत्री ने कंपनियों से लाभांश वितरण कर वसूलने का प्रावधान खत्म करने की पुरानी मांग मान ली मगर बाजार को यह बजट पसंद नहीं आया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 987.96 अंक और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 373.85 अंक गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार प्रतिभागियों का कहना है कि विनिवेश के लंबे-चौड़े कार्यक्रम का नकदी की उपलब्धता पर असर पड़ने और बजट से मांग नहीं बढ़ने की चिंता के कारण ऐसा हुआ।

■ शेष पृष्ठ 8 पर

सेंसेक्स	
पिछला बंद	40,723.49
बंद	39,735.53
% बदलाव	-2.4 ▼

निफ्टी 50	
पिछला बंद	11,962.1
बंद	11,661.9
% बदलाव	-2.5 ▼

खास बातें

- एलआईसी में हिस्सा बेचेगी सरकार
- कंपनियों को लाभांश वितरण कर से राहत
- बैंक जमा बीमा 1 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपये
- रक्षा बजट बढ़कर 3.23 लाख करोड़ रुपये
- कृषि, संबंधित कार्यों के लिए 2.83 लाख करोड़ रु.
- कृषि क्षेत्र को 15 लाख करोड़ ऋण आवंटन का लक्ष्य
- रेलवे के लिए 70,000 करोड़ रुपये आवंटित
- रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय मामूली बढ़ा
- परिवहन अवसंरचना के लिए 1.7 लाख करोड़ रु.
- नॉमिनल जीडीपी दर 10 प्रतिशत रहने का अनुमान
- प्राप्तियां 22.46 लाख करोड़ रु. रहने का अनुमान
- व्यय 30.42 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान
- सरकार ले सकती है 5.36 लाख करोड़ उधार
- आधार पर तत्काल आवंटित होगा पैन
- कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई सीमा अब 15 प्रतिशत
- बजट में सब्सिडी पर अंकुश लगाने का प्रयास
- आईडीबीआई बैंक में शेष हिस्सेदारी भी बिकेगी

...मगर बाजार नहीं हुआ खुश

बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और दबाव वाले क्षेत्रों की मदद के लिए अपेक्षाकृत कम उपायों की घोषणा से बाजार निराश हुआ। बेंचमार्क सूचकांकों का प्रदर्शन बजट के दिन 11 वर्षों में सबसे खराब रहा। बीएसई सेंसेक्स 988 अंक लुढ़ककर 39,736 पर बंद हुआ, वहीं एनएसई निफ्टी 300 अंक टूटकर 11,662 पर बंद हुआ। पिछले तीन साल के दौरान एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है और बजट के दिन 2009 के बाद बाजार का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आईटी सूचकांक को छोड़कर बीएसई के सभी क्षेत्रों के सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। राजकोषीय घाटा बढ़ने की चिंता और अगले वित्त वर्ष के 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य ने निवेशकों के उत्साह पर असर हुआ। पृष्ठ3

अन्दर के पृष्ठों पर

संपूर्ण विश्लेषण
बजट और आप 2
बजट और बाजार 3
बजट और कारोबार 4
बजट और अर्थव्यवस्था 6
संपादकीय 7
बजट और राजनीति 14

आज का सवाल

क्या बजट में अर्थव्यवस्था में सुधार के किए गए हैं पर्याप्त उपाय

www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा
क्या कर संग्रह में कमी का बजट में दिखेगा असर? हां 83.33% नहीं 16.67%

बाजार को भाएगा बजट

बजट के खास पहलुओं पर बात करते हुए वित्त मंत्री **निर्मला सीतारमण** ने स्वीकार किया कि चालू वित्त वर्ष में विनिवेश लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है, लेकिन उन्हें यकीन है कि अगले छह महीने में इसमें तेजी आ जाएगी। उन्होंने राजकोषीय मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौतियों और नई कर प्रणाली पर भी बात की। मुख्य अंश:

● व्यक्तिगत आयकर में दो तरह की कर व्यवस्था के पीछे क्या तर्क है?

सवाल — जवाब

● हम कर ढांचा सरल बनाने के लिए दरों को कम से कम करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि लोगों के पास पैसा रहे। हमने कर दर में उसी तरह कटौती की, जिस तरह हमने पिछले साल कॉरपोरेट कर में की थी। हम चाहते हैं कि दरें घटें और अनुपालन के मामले में जो पेचीदगी है, वह भी खत्म हो जाए। ढेर सारी रियायतों और छूटों से मुश्किलें खड़ी होती हैं और लोग कर बचाने के लिए विशेषज्ञों की राय लेते रहते हैं। हमारे दो मकसद थे: आयकर को सरल बनाना और घटना। अच्छा तो यही था कि नई कर प्रणाली में कोई छूट ही नहीं होती मगर हमने ऐसी छूट बरकरार रखीं, जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। आगे जाकर हम सभी छूट और रियायत खत्म कर देंगे ताकि आयकर का पूरा ढांचा सरल हो जाए।

● विनिवेश के मोर्चे पर सरकार को क्या उम्मीद है?

● मैंने विनिवेश का लक्ष्य जुलाई में तय किया था। जुलाई और जनवरी के बीच वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने जमकर कोशिश की हैं और अगले कुछ महीनों में विनिवेश के कई प्रयास सफल होंगे। वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है, इसलिए मैं बाजार को अटकलें लगाने नहीं दे सकती थी। जुलाई से अब तक बहुत सारा अटका काम पूरा हो गया है और अगले वित्त वर्ष में फायदे दिखेंगे।

● राजकोषीय घाटे के नए लक्ष्य पर आप क्या कहेंगी?

● बजट अनुमान में हमने इसे जीडीपी के 3.3 फीसदी पर रखा था। इसकी वजह यह थी कि खपत मांग और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा धन रखने की चुनौती थी और आपदा, अनुपालन तथा जीएसटी संग्रह कम होने के कारण राजस्व पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा सका। कॉरपोरेट कर में कटौती के कारण राजस्व में और भी कमी हो गई। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ा। लेकिन पिछले तीन महीनों में जीएसटी संग्रह अच्छा रहा है और अधिक से अधिक कंपनियां कॉरपोरेट कर व्यवस्था के तहत आ रही हैं तो राजस्व संग्रह बेहतर रहेगा।

● मगर बजट पर शेयर बाजार का रुख नकारात्मक रहा है...

● मैं शेयर बाजार को एक पूरा दिन देखना चाहती हूं। आज शनिवार है तो हो सकता है कि सभी श्रेणियां पूरी तरह काम नहीं कर रही हों। हम सोमवार का इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि बजट और खास तौर पर बॉन्ड बाजार के लिए हमारी घोषणाओं का बाजार पर अच्छा प्रभाव होगा।

मेरा बजट

तसनीम जकारिया मेहता
कला इतिहासकार एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता

क्या बजट से अर्थव्यवस्था की चिंता दूर हुई है?

बजट में मांग पैदा करने और अर्थव्यवस्था को ताकत प्रदान करने के लिहाज से पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए।

क्या यह लोक-लुभावन बजट है?

सरकार ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति घटाने का वादा किया है जिनमें उसे ज्यादा दक्षता हासिल नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यवश, हम ऐसा होते नहीं देख रहे हैं। खासकर, संस्कृति के क्षेत्र में, सरकार को विशेषज्ञों को स्थानों और संग्रहालयों के विकास का जायजा लेने की अनुमति देनी चाहिए।

क्या रोजगार पैदा होंगे?

मेरा मानना है कि वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी में कौशल पर काफी कुछ कहा, लेकिन इन क्षेत्रों को बुनियादी स्तर की शिक्षा जरूरी है जिससे ऐसी मेधाओं को विकसित करने में समय लगेगा। इसके विपरीत, बेहद छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कारीगर का जिक्र नहीं किया गया, जो किसान और साथ ही शिल्पकार भी है। हमारा शिल्प क्षेत्र गरीबों के बड़े तबके को रोजगार मुहैया कराता है और उन्हें बाजार तक पहुंच में मदद मुहैया कराने की सख्त जरूरत है।

बजट में आपको क्या अच्छा या बुरा लगा?

पूरे देश में संग्रहालयों की लोकप्रियता कमजोर हो रही है और हमारे कई खास संग्रह को नुकसान पहुंच रहा है। यह अच्छी बात है कि सरकार संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान बनाने पर विचार कर रही है, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में ऐसे कम से कम चार संस्थान होने चाहिए। मैं लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य और विवाह उम्र की समीक्षा जैसे प्रयासों को लेकर खुश हूं। महिलाओं की समस्याओं के प्रति पुलिस और अधिकारियों को ज्यादा जागरूक होना चाहिए।

बजट प्रभाव

व्यक्तिगत आय कर को आसान बनाया गया है और इसमें कमी की गई है। इससे लोगों के पास खर्च योग्य आय में इजाफा होगा

"बजट में कारोबार जगत का आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय किए गए हैं, लेकिन व्यक्तिगत करदाता निराश हुए हैं। उपभोक्ता मांग बढ़ने की उम्मीद कम है।"

किरण मजूमदार शॉ, सीएमडी, बायोकॉन

ज्यादा फायदा चाहिए तो पहले जैसा कर कटाइए

आयकर

कई करदाताओं के लिए, पुरानी व्यवस्था से जुड़े रहना फायदेमंद साबित हो सकता है

बजट 2020 के बाद अब करदाताओं के लिए दो कर व्यवस्थाएं मौजूद होंगी। पुरानी व्यवस्था बरकरार रहेगी जिसमें ऊंची कर दरें (आय के कई स्तरों परं लागू हैं, लेकिन इसमें विभिन्न कर रियायतें और छूट प्रदान की गई हैं। वहीं वित्त मंत्री द्वारा पेश नई कर व्यवस्था में कर दर कई लोगों के लिए कम रहेगी, लेकिन करदाता किसी कर छूट या रियायत का लाभ उठाने में सक्षम नहीं होंगे। विश्लेषकों का कहना है कि कर प्रणाली अब करदाता-केंद्रित हो गई है। हरेक करदाता को वित्त वर्ष के शुरू में अपनी स्थिति का अध्ययन करना होगा और उसके बाद यह निर्णय लेना होगा कि उसे नई कर व्यवस्था अपना चाहिए या पुरानी।

कई करदाताओं के लिए, पुरानी व्यवस्था से जुड़े रहना फायदेमंद साबित हो सकता है। क्लियरटैक्स के संस्थापक एवं मुख्य कार्याधिकारी अर्चित गुप्ता कहते हैं, 'हमारे विश्लेषणों से पता चला है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा कर लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए पुराने कर स्लैब के साथ जुड़े रहना उचित होगा। ऐसे लोगों को नई कर व्यवस्था का चयन नहीं करना चाहिए।'

करदाताओं के लिए कई तरह की छूट और रियायतें उपलब्ध हैं। वेतनभोगी कर्मचारी हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) और लीव ट्रेवल अलाउंस (एलटीए) का लाभ उठा सकते हैं। आवास ऋण ले चुके लोग अपनी ईएमआई के ब्याज वाले हिस्से और मूल रकम पर भी (धारा 80सी के तहत) 2 लाख रुपये तक की कर छूट का लाभ ले सकते हैं। धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट हासिल है। हर साल चुकाए जाने वाले स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट धारा 80डी के तहत बढ़कर 75,000 रुपये, अपने मूल परिवार के लिए प्रीमियम भुगतान पर 25,000 रुपये और अपने माता-पिता (यदि वे वरिष्ठ नागरिक हैं) पर चुकाए गए प्रीमियम के लिए 50,000 रुपये तक हो सकती है। 50,000 रुपये तक की अन्य छूट धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उपलब्ध हे। इसी तरह के कई और लाभ भी मौजूद हैं।

कर व्यवस्था का चयन में समस्या पैदा करने वाला एक प्रमुख कारक इसकी जटिल गणना से जुड़ा होगा। कुछ छूट की सीमा के अभाव की वजह से करदाताओं को यह तय करने में अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि उनके लिए कौन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी। गुप्ता का कहना है, 'धारा 80ई के तहत शैक्षिक ऋण पर छूट हासिल है और इसमें कोई ऊपरी सीमा नहीं है।'

करदाता उस ब्याज आय की किसी भी मात्रा के लिए कर छूट का दावा कर सकता है जो उसने वित्त वर्ष में चुकाई हो। वहीं अपने बच्चे की विदेश शिक्षा की जरूरत पूरी करने के लिए बड़ा शैक्षिक ऋण लेने वालों के लिए पुरानी कर व्यवस्था से जुड़े रहना समझदारी भरा निर्णय हो सकता है।

जहां नई कर व्यवस्था सरल है, लेकिन करदाता को अपनी स्थिति के आधार यह निर्णय लेना है कि उसे इसका चयन करना है या नहीं। टैक्समान डॉटकॉम के डीजीएम नवीन वाधवा कहते हैं, 'यह पता कर लें कि आप कौन सी कर छूट एवं रियायत पाने के हकदार हैं। इसके बाद इसकी गणना करें कि क्या आपकी कर देनदारी नई व्यवस्था या फिर पुरानी व्यवस्था में कम हो जाएगी।' वह कुछ आंकड़ों का भी उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं, 'यदि आपकी आय 8.5 लाख रुपये से कम है और आप सिर्फ 80सी के तहत छूट का दावा करना चाहते हैं तो नई कर व्यवस्था को न अपनाएं। दूसरी तरफ, यदि आपकी आय 8.5 लाख रुपये से ज्यादा है, और आपने सिर्फ धारा 80सी के तहत छूट का दावा किया है तो आपके लिए नई व्यवस्था का चयन करना समझदारी भरा हो सकता है।'

अब 5 लाख रुपये तक जमा का बीमा

बजट में सरकार ने जमाकर्ता के लिए जमा बीमा कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'मैं यह बताना चाहती हूं कि सभी शिड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की सेहत पर नजर रखने के लिए एक मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया गया है और जमाकर्ताओं की पूंजी सुरक्षित है।' जमा बीमा कवर में वृद्धि 27 साल बाद की गई है। मई 1993 में जमा कवर 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया था। अब तक 1 लाख रुपये के जमा बीमा कवर के साथ, भारत में ब्रिक देशों की तुलना में सबसे कम जमा बीमा कवर था और पंजाब तथा महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में संकट के बाद जमा बीमा कवर की मांग बढ़ी है।

नई कर व्यवस्था के तहत छूट

- मृत्यु या सेवानिवृत्ति लाभ
- पेंशन की प्रतिपूर्ति
- सेवानिवृत्ति पर अवकाश का पैसा
- सेवानिवृति रकम
- वीआरएस पर मिलने वाली रकम 5 लाख रुपये तक
- ईपीएफ में नियोक्ता का योगदान
- राष्ट्रीय पेंशन योजना पूरी होने पर प्राप्त रकम
- शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति के तौर पर प्राप्त रकम

प्रत्यक्ष कर विवादों के लिए राहत योजना

काला धन

अगर बकाया कर का भुगतान 31 मार्च तक किया जाता है तो ब्याज और जुर्माना माफ हो जाएंगे। प्रत्यक्ष कर विवादों में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि फंसे होने का अनुमान

सरकार ने पांच महीनों (30 जून तक) के लिए 'विवाद से विश्वास' योजना शुरू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में कहा इस योजना के जरिये करदाता अपने आयकर से संबंधित विवादों को सुलझा सकते हैं। प्रस्तावित योजना के तहत अगर करदाता 31 मार्च तक भुगतान करता है तो उसे केवल विवादित कर की राशि चुकानी पड़ेगी और ब्याज एवं जुर्माना पूरी तरह माफ हो जाएगा। ऐसे विवादित जुर्माने, ब्याज और फीस, जिनका विवादित कर से कोई लेनादेना नहीं है, उनके समाधान के लिए करदाता को केवल 25 फीसदी भुगतान करना होगा। अगर भुगतान 31 मार्च 2020 के बाद किया जाता है तो करदाता को विवादित कर की 110 फीसदी राशि और जुर्माने, ब्याज एवं फीस की राशि का 30 फीसदी चुकाना होगा।

यह योजना अप्रत्यक्ष कर के मुकदमों की 'सबका विश्वास योजना 2019' के समान है। इस योजना से राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी को रोकने में मदद मिल सकती है। इससे विभिन्न मंचों पर लंबे समय से चल रहे मुकदमों में अटके कर राजस्व को हासिल करने में मदद मिलेगी। विभाग के सूत्रों ने कहा कि इन विवादों से जुड़ी कुल रकम करीब पांच से छह लाख करोड़ रुपये हो सकती है।

मंत्री ने कहा, 'हमारी सरकार ने कर मुकदमों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पिछले बजट में 'सबका विश्वास योजना' की घोषणा की गई थी, जिससे 1,89,000 मामलों को सुलझाने में मदद मिली। मैं अप्रत्यक्ष कर से संबंधित 'सबका विश्वास योजना' की तर्ज पर इस साल प्रत्यक्ष करों के मुकदमों को कम करने के लिए एक योजना लाने का प्रस्ताव रखती हूं।' उन्होंने कहा कि विभिन्न अपीलीय फोरम कमीशनर (अपील्स), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में 4,83,000 प्रत्यक्ष कर के मामले लंबित हैं।

ध्रुव एडवाइजर्स एलएलपी के सीईओ दिनेश कानाबार ने कहा, 'यह विवादों को निपटाने का बहुत रोचक प्रावधान है। सभी लंबित विवादों के करों का भुगतान करने वालों से 31 मार्च से पहले बिना ब्याज एवं जुर्माने के कर लेने का उपाय बहुत से करदाताओं के लिए आकर्षक होगा।'

इसके अलावा मंत्री ने फेसलैस स्क्रूटनी एसेसमेंट के अलावा फेसलैस अपील का भी प्रस्ताव रखा। इससे इस प्रक्रिया में मानवीय दखल समाप्त हो जाएगा और अनुपालना, पारदर्शिता और बेहतर वैश्विक तरीकों को अपनाना संभव हो सकेगा। हालांकि विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि इससे अनिश्चितता पैदा हो सकती है क्योंकि इससे व्यक्तिगत सुनवाई की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।

इसके अलावा बजट में करदाताओं के लिए चार्टर और इसे आयकर अधिनियम में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, 'किसी भी कर प्रणाली में करदाताओं और प्रशासन के बीच भरोसे की जरूरत होती है। यह केवल तभी संभव है जब करदाताओं के अधिकारों को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा।'

रियल एस्टेट खरीदारों और विक्रेताओं को मिली राहत

रियल्टी

सर्किल दर के बिक्री कीमत के पार जाने की स्थिति में कर लाभ 105 प्रतिशत से बढ़ाकर 110 प्रतिशत किया गया

बजट में उन हालात में खरीदारों और विक्रेताओं को राहत दी गई है जब रियल एस्टेट सौदे के लिए घोषित कीमत सर्किल दर की तुलना में कम हो।

शुरू में, यदि यह घोषित वैल्यू सर्किल वैल्यू की तुलना में 5 प्रतिशत से ज्यादा कम होती थी, तो इस अंतर पर खरीदार और विक्रेता दोनों पर कर लगता था। अब यह अंतर 10 प्रतिशत के पार होने की स्थिति में कर लगेगा। सर्किल दर वह न्यूनतम दर है जिस पर रियल एस्टेट सौदे को पंजीकृत कराया जा सकता है। यह दर राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है।

देश के विभिन्न हिस्सों में रियल एस्टेट बाजारों में गिरावट आई है या वे कई वर्षों से स्थिर बने हुए हैं। साथ ही, खासकर नकदी वाले सौदों से जुड़े इलाकों में (जहां सरकार मानती है कि सौदों का बड़ा हिस्सा नकदी में होता है) में सर्किल दर बढ़ी है, जिसका मकसद कर चोरी को रोकना है। सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए भी समय समय पर सर्किल दर में इजाफा किया है। इन बदलावों के परिणामस्वरूप, देश के कई हिस्सों में सर्किल दर बाजार दर की तुलना में काफी ऊंची हो गई है।

कोलियर्स इंटरनैशनल में पूंजी बाजार और निवेश सेवाओं के राष्ट्रीय निदेशक गगन रनदेव ने कहा, 'कर छूट 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करना खरीदारों और विक्रेताओं के लिए एक बड़ी राहत है। अब ज्यादा सौदों पर कर लगने से बच जाएगा।'

हमें उदाहरण के साथ इसे समझने की कोशिश करनी होगी। मान लीजिए कि किसी इलाके में बिक्री का सौदा 100 रुपये में हुआ है। शुरू में, सर्किल दर 105 रुपये होने पर खरीदार और विक्रेता सुरक्षित थे। अब यह कर सुरक्षा बढ़ाकर 110 रुपये की दर के लिए की गई है। लेकिन यदि सर्किल कीमत 150 रुपये है तो यह प्रावधान उपयोगी नहीं होगा और इससे संबद्ध सौदे में शामिल लोगों को सर्किल दर पर कर चुकाना होगा। एलऐंडएल पार्टनर्स में पार्टनर लोकेश शाह कहते हैं, 'खरीदार को इस अंतर पर मार्जिनल आयकर दर लगेगी और विक्रेता को पूंजीगत लाभ कर चुकाना होगा।'

बदलाव की कोशिश

- सर्किल दर को लेकर खरीदारों और विक्रेताओं को दी गई है राहत

कर नहीं चुकाने वाले एनआरआई पर सख्ती

एनआरआई

कर आकलन को ध्यान में रखकर एनआरआई को न्यूनतम कर दरों वाले देश का चयन करने की जरूरत होगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नई कर व्यवस्था पेश कर कुछ भारतीय करदाताओं को भले ही राहत प्रदान की है, लेकिन अभी भी वे प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल नहीं रही हैं। आरएसएम इंडिया के संस्थापक चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराणा ने कहा, 'वह भारतीय नागरिक, जो किसी अन्य देश या क्षेत्र में कर चुकाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, उसे भारत का निवासी समझा जाएगा।' इसका मतलब है कि यदि भारतीय नागरिक दुनिया में किसी अन्य देश का निवासी नहीं है, तो उसे भारत का निवासी माना जाएगा और उसकी वैश्विक आय पर कर लगेगा।

डीएसके लीगल में पार्टनर नंद किशोर कहते हैं, 'आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 कर के उद्देश्य के लिए भारत में करदाता के निवास को परिभाषित करती है। अब इस धारा में ऐसे प्रभावी प्रावधान शामिल करने के लिए इसमें संशोधन किया गया है जो भारत के किसी निवासी को किसी अन्य देश में कर देयता से अलग करते हैं।'

यह बदलाव क्यों: यह एक महत्वपूर्ण कदम है। एनए शाह, एसोसिएट्स एलएलपी में फाउंडिंग पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक शाह कहते हैं, 'मौजूदा समय में, यदि कोई व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है या भारतीय मूल का व्यक्ति है) भारत में इस तरह से रहने में सफल रहा हो जैसे कि वह लगातार प्रवासी के तौर पर रहा, तो वह भारत में अपनी वैश्विक आय पर कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं है। अभी तक अमीर निवेशकों के लिए यह साबित करना आसान था कि वह न तो किसी अन्य देश में और न ही भारत में कर चुकाने के लिए बाध्य हैं।' अब भविष्य में ऐसे व्यक्ति की सभी आय (घरेलू और वैश्विक, दोनों) पर भारत में कर लगेगा।

क्या प्रभाव पड़ेगा: सुराणा का कहना है, 'अब ऐसे व्यक्ति प्रभावित होंगे, जो व्यावसायिक कारणों से दुनियाभर की यात्रा करते हैं और यात्रा से जुड़े सभी देशों में अपने प्रवासी दर्जे को बनाए रखते हैं। अब उन्हें भारत का निवासी समझा ज ाएगा और भारत में उनकी वैश्विक आय कराधान के दायरे में आएगी।'

संयुक्त अरब अमीरात और अन्य शून्य कर वाले देशों के निवासियों के लिए, इसका प्रभाव नहीं पड़ सकेगा, लेकिन कर की देयता के संदर्भ में मुकदमेबाजी और आयकर नहीं चुकाने जैसे मामले फिर से सामने आएंगे।

क्या करना चाहिए: शाह का कहना है, 'भारत के नागरिक के तौर पर प्रवासियों को अब कर आकलन के लिए न्यूनतम कर दर वाले देश का चयन करना उचित होगा।'

चित्रांकनः अजय मोहंती

बजट संक्षेप में

नया टैक्सपेयर्स चार्टर बनेगा

करदाताओं और प्रशासन के बीच विश्वास पैदा करने के मकसद से, टैक्सपेयर्स चार्टर अपनाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की अनिवार्यता के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इस चार्टर के कंटेंट का विवरण जल्द जारी कर दिया जाएगा।

प्रत्यक्ष करों में विवाद निपटान के लिए योजना

प्रस्तावित 'विवाद से विश्वास' योजना के तहत करदाता को सिर्फ विवादित कर चुकाना होगा और उसे 31 मार्च 2020 तक भुगतान से संबंधित ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी। 31 मार्च, 2020 के बाद इस योजना पर अमल करने वालों को कुछ अतिरिक्त रकम चुकानी होगी। यह योजना 30 जून, 2020 तक उपलब्ध रहेगी।

आधार के जरिये तुरंत पैन

पिछले बजट में वित्त मंत्री ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार की विनिमेयता पर जोर दिया था, जिसके लिए जरूरी नियम पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। पैन आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक जासान बनाने के प्रयास में सरकार ने जल्द ही ऐसी व्यवस्था लाने की योजना बनाई है जिसके तहत आवेदन फॉर्म भरे बगैर ही आधार के माध्यम से पैन ऑनलाइन आवंटित कर दिया जाएगा।

1 अप्रैल से जीएसटी रिटर्न आसान

आसान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न पर 1 अप्रैल, 2020 से अमल किया जाएगा। फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है। शून्य रिटर्न के लिए एसएमएस-आधारित फाइलिंग, रिटर्न-प्री फाइलिंग, उन्नत इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे फीचर्स के साथ अब रिटर्न फाइलिंग आसान होगी।

बजट प्रभाव

कंपनियों के लिए डीडीटी खत्म करने से विदेशी निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को होगा लाभ। प्रवर्तक लाभांश की जगह पुनर्खरीद को दे सकते हैं तवज्जो

"डीडीटी को हटाने, कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश सीमा बढ़ाने से निवेश माहौल में सुधार आएगा।"

रवनीत गिल, एमडी एवं सीईओ, येस बैंक

दलाल पथ को रास नहीं आया बजट

शेयर बाजार

सेंसेक्स और निफ्टी में आई करीब 2.5 फीसदी की गिरावट, 2009 के बजट के बाद बाजार का सबसे खराब प्रदर्शन

बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और दबाव वाले क्षेत्रों की मदद के लिए अपेक्षाकृत कम उपायों की घोषणा से बाजार निराश हुआ। यही वजह रही कि बेंचमार्क सूचकांकों का प्रदर्शन बजट के दिन 11 वर्षों में सबसे खराब रहा और निवेशकों ने जमकर बिकवाली की।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 988 अंक लुढ़ककर 39,736 पर बंद हुआ, वहीं नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 300 अंक टूटकर 11,662 पर बंद हुआ। पिछले तीन साल के दौरान एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है और बजट के दिन 2009 के बाद बाजार का यह सबसे खराब प्रदर्शन रहा। आईटी सूचकांक को छोड़कर बीएसई के सभी क्षेत्रों के सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई।

राजकोषीय घाटा बढ़ने की चिंता और अगले वित्त वर्ष के 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य ने निवेशकों की धारणा प्रभावित की है। निवेशकों को डर है कि विनिवेश का बड़ा लक्ष्य और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का प्रस्तावित मेगा आईपीओ से द्वितीयक बाजार में एक तरह से हड़कंप मच सकता है। इसके साथ ही दीर्घावधि पूंजीलाभ कर (एलटीसीजी) और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) ने भी बाजार के मनोबल को कम करने का काम किया।

वित्त मंत्री के भाषण के साथ कारोबार के दौरान सेंसेक्स में 1,275 अंक का उतार-चढ़ाव देखा गया। पिछले कुछ बजट की तुलना में इस बार बाजार में उतार-चढ़ाव कुछ ज्यादा ही रहा। आईआईएफएल के संस्थापक और चेयरमैन निर्मल जैन ने कहा, 'बाजार को बजट से काफी उम्मीदें थीं जिसकी वजह से बाजार थोड़ा निराश हुआ।'

शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के मुख्य कार्याधिकारी जयदीप अरोड़ा ने कहा, 'अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बाजार घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जैसे बड़े उपायों की उम्मीद कर रहा था।' बजट से पहले बाजार में तेजी का रुख था और कोरोना वायरस की वजह से गिरावट आने से पहले वह सर्वकालिक उच्च स्तर पर भी पहुंच गया था।

जानकारों का कहना है कि बजट ने निवेशकों को निराश किया। रियल्टी और पूंजीगत वस्तुओं से जुड़ी कंपनियों में बड़ी गिरावट आई और इस क्षेत्र के सूचकांक क्रमश: 7.8 फीसदी और 4.8 फीसदी गिरावट पर बंद हुए।

निवेशक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा कंपनियों के लिए कुछ राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे थे लेकिन बजट में इन क्षेत्रों के लिए कुछ खास नहीं रहा। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने कहा, 'एनबीएफसी क्षेत्र की खस्ताहालत को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए राहत की उम्मीद की जा रही थी लेकिन बजट में न तो इस क्षेत्र के लिए और न ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर ध्यान नहीं दिया गया। अव्यवहारिक उम्मीद और स्पष्टता की कमी के कारण बाजार में गिरावट आई है।'

आयकर में प्रस्तावित बदलाव से सूचीबद्ध बीमा कंपनियों में भी गिरावट देखी गई क्योंकि निवेशकों में डर है कि इन कंपनियों की रेटिंग घट सकती है। मैक्स फाइनैंशियल सर्विसेस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में 10-10 फीसदी की गिरावट आई। बजट में सिगरेट पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव से सेंसेक्स कंपनियों में सबसे ज्यादा 7 फीसदी गिरावट आईटीसी में देखी गई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस और हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 4 फीसदी और टीसीएस में 2 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। बाजार के भागीदारों का कहना है कि लाभांश वितरण कर में कटौती से ज्यादा नकदी वाली कंपनियों को फायदा होगा।

कुल मिलाकर बीएसई में 1,750 शेयर गिरावट पर और 589 बढ़त पर बंद हुए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1,200 करोड़ रुपये की बिकवाली की।

सेंसेक्स में कौन चढ़ा, किसे नुकसान

चढ़ने वाले शेयर	कीमत (रुपये में)	बदलाव (फीसदी)
टीसीएस	2,165.1	4.1
एचयूएल	2,073.6	1.9
टेक महिंद्रा	807.5	1.5
इन्फोसिस	780.3	0.5
नेस्ले इंडिया	15,425.8	0.4
गिरने वाले शेयर		
आईटीसी	218.9	-7.0
एलऐंडटी	1,287.3	-6.0
एचडीएफसी	2,270.8	-5.9
भारतीय स्टेट बैंक	303.2	-4.8
ओएनजीसी	104.4	-4.2

स्रोत : एक्सचेंज/ब्लूमबर्ग संकलन : बीएस रिसर्च ब्यूरो

डीडीटी : कंपनियों को राहत, शेयरधारकों की आफत

लाभांश वितरण कर

बजट में लाभांश वितरण कर का बोझ कंपनियों से हटाकर शेयरधारकों पर डाला गया है। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और छोटे निवेशकों को होगा फायदा, प्रवर्तकों की बढ़ेगी मुश्किल

डीडीटी खत्म करने से सरकार को सालाना करीब 25,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना होगा लेकिन शेयर बाजार को इससे आकर्षक बनाने में मदद मिलेगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लाभांश वितरण कर (डीडीटी) को खत्म करने की शेयर बाजार की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा कर दिया। हालांकि इसमें थोड़ा पेच हैं क्योंकि नए प्रावधान के तहत इसका भार निवेशकों पर डाला गया है। ऐसे में उच्च कर दायरे कर दायरे में आने वाले निवेशकों पर ज्यादा कर बोझ बढ़ेगा। सरकार ने डीडीटी को कंपनियों से तो खत्म कर दिया लेकिन इसे प्राप्त करने वालों को यह कर देना होगा और अति धनाढ्यों पर इसकी प्रभावी दर 43 फीसदी हो सकती है।

सीतारमण ने कहा, 'भारतीय बाजार को निवेश का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिहाज से यह एक और सकारात्मक कदम है।' उन्होंने कहा कि डीडीटी को खत्म करने से सरकार को सालाना करीब 25,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान उठाना होगा लेकिन यह भारतीय शेयर बाजार को ज्यादा आकर्षक बनाएगा।

मौजूदा व्यवस्था के तहत लाभांश की घोषणा करने वाली कंपनी को 15 फीसदी की दर से डीडीटी देना होता है, जिसकी प्रभावी दर अधिभार आदि को मिलकार 17.64 फीसदी है, वहीं लाभांश पाने वालों को अतिरिक्त 10 फीसदी कर देना होगा अगर किसी वित्त वर्ष में उसे 10 लाख रुपये से अधिक का लाभांश मिलता है।

विशेषज्ञों ने कहा कि कंपनियों के साथ ही विदेशी निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, होल्डिंग कंपनियों और कम कर दायरे वाले निवेशकों को भी लाभ होगा। दूसरी ओर घरेलू प्रवर्तकों और 30 फीसदी कर दायरे में आने वाले व्यक्तिगत करदाताओं पर इसका बोझ पड़ेगा।

इस घोषणा से कंपनियों की ओर से लाभांश भुगतान में तेजी आ सकती है लेकिन निवेशकों को इससे होने वाली वास्तविक प्राप्ति कम हो सकती है। डीडीटी को हटाने का निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब कुछ महीने पहले ही कॉरपोरेट कर की दर को 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी की गई है। अर्थव्यवस्था में नरमी के दौर में इन दोनों कदमों से भारतीय उद्योग जगत की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

ईवाई इंडिया में नैशनल टैक्स लीडर सुधीर कपाड़िया ने कहा, 'डीडीटी को खत्म करने से कॉरपोरेट कर ढांचे में सुधार को सही मायने में पूरा माना जा सकता है और भारत को यह दुनिया का सर्वाधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाएगा। इस कदम से भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेशकों के इक्विटी पर रिटर्न में उल्लेखनीय सुधार होगा।'

डीडीटी, दीर्घावधि पूंजी लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर सहित अन्य करों की वजह से घरेलू बाजारों में कर ढांचा दुनिया में सबसे उच्च माना जाता था। केपीएमजी इंडिया में पार्टनर विवेक गुप्ता ने कहा, 'शेयरधारकों पर करदेयता वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य व्यवस्था के तहत आने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित अधिकांश करदाताओं को इसका लाभ मिलेगा।'

डीडीटी क्रेडिट की उपलब्धता नहीं होने से विदेशी निवेशकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था क्योंकि उन्हें कई कर देने होते हैं। दिलचस्प है कि नए कर ढांचे में बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब घरेलू प्रवर्तकों की तुलना में अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न हासिल करने में सक्षम होंगे।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी के पास आयकर से पहले 1,000 रुपये हैं जिसे वह लाभांश के तौर पर देती है तो वर्तमान में कंपनी डीडीटी के बाद 850 रुपये का ही भुगतान कर पाती है। इसके साथ ही प्रवर्तकों को प्रति 100 रुपये लाभांश प्राप्ति पर 10 रुपये कर देना होता है। नई व्यवस्था के तहत कंपनी अब पूरा 1,000 रुपये शेयरधारकों को दे सकती है। हालांकि प्रवर्तकों को प्रति 100 रुपये के प्राप्त लाभांश पर 43 रुपये कर देना होगा।

बाजार के भागीदारों का कहना है कि कर ढांचे में बदलाव से नकदी की ढेर पर बैठी ककंपनियां लाभांश की जगह पुनर्खरीद को तवज्जो दे सकती हैं क्योंकि यह प्रवर्तक के अनुकूल उपाय होगा। शेयर पुनर्खरीद चालू वित्त वर्ष में उतनी आकर्षक नहीं रह गई थी क्योंकि इस पर 20 फीसदी का पुनर्खरीद कर लगाया गया था। केंद्र सरकार ने नई कर व्यवस्था में पुनर्खरीद कर के बारे में कुछ नहीं कहा है। इससे पिछले दो वित्त वर्ष में कंपनियों ने रिकॉर्ड पुनर्खरीद की थी।

थोड़ी राहत मगर उम्मीद पर खरा नहीं उतरा बजट

दिशासूचक

बाजार अर्थव्यवस्था में तेजी के उपायों की उम्मीद कर रहा था लेकिन बजट में इस दिशा में ठोस उपाय नहीं होने से बढ़ी निराशा

बाजार हुआ निराश

- बजट ने बाजार को किया निराश
- अर्थव्यवस्था को गति देने के उपायों की थी उम्मीद
- लेकिन बजट ने अधिकांश उम्मीदों पर फेरा पानी
- बजट घोषणाओं से अर्थव्यवस्था को नहीं मिलेगी गति
- लाभांश वितरण कर से खपत हो सकती है प्रभावित

ऐसे वक्त जब भारत की जीडीपी वृद्धि दर एक दशक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, बाजार राजकोषीय फिसलन की कीमत पर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़े उपायों की उम्मीद कर रहे थे। उच्च विकास दर और कंपनियों की बेहतर कमाई से बाजारों को उच्च मूल्यांकन बनाए रखने और ज्यादा विदेशी तथा घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलती।

पिछले साल सितंबर में कंपनी कर की दरों में कटौती तथा रियल्टी और एनबीएफसी क्षेत्रों को उबारने के लिए उठाए गए कदमों से बाजारों में उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन बजट ने इनमें से अधिकांश उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसमें कंपनियों की कमाई बढ़ाने के उपायों का अभाव रहा। बाजार की प्रतिक्रिया भी इसका संकेत है।

आनंद राठी शेयर्स ऐंड स्टॉक ब्रोकर्स के मुख्य अर्थशास्त्री और कार्यकारी निदेशक सूजन हाजरा कहते हैं, 'अगर कोई अर्थव्यवस्था में तेजी के उपायों की उम्मीद कर रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया गया है। लेकिन बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं।'

ऐक्सिस सिक्योरिटीज के फंडामेंटल रिसर्च प्रमुख पंकज बोबडे ने कहा, 'बाजार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कुछ ठोस उपायों की उम्मीद कर रहा था लेकिन सरसरी नजर में देखने पर ऐसा नहीं लगता है।'

अधिकांश विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में घोषित उपायों का अर्थव्यवस्था और कंपनियों की कमाई पर बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने नई वैकल्पिक आय कर व्यवस्था से 40 हजार करोड़ रुपये का फायदा मिलने का दावा किया है लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा। साथ ही लाभांश वितरण कर को खत्म नहीं किया गया है बल्कि इसमें कुछ बदलाव किया गया है। इसमें भी अब लाभांश पाने वाले लोगों को कर देना होगा जिससे उनके हाथ में कम पैसे आएंगे। इससे खपत प्रभावित हो सकती है।

शेयरखान के मुख्य कार्याधिकारी जयदीप अरोड़ा कहते हैं, 'व्यक्तिगत आय कर की दरों में कटौती का प्रभाव सीमित रह सकता है क्योंकि इसके लिए आपको अब तक मिलने वाली छूट छोड़नी होगी।'

कुछ विशेषज्ञ कम कर संग्रह और जीडीपी विकास दर में गिरावट को देखते हुए बजट को सकारात्मक मानते हैं। कोटक म्युचुअल फंड की इक्विटी प्रमुख शिवानी कूरियन ने कहा, 'कम कर संग्रह और आर्थिक विकास में कमी के बावजूद सरकार ने संतुलित बजट पेश किया है। सरकार ने एलआईसी को सूचीबद्ध कराने और आईडीबीआई में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। साथ ही एयर इंडिया और अन्य कंपनियों में भी विनिवेश का प्रस्ताव है। अगर इनमें से एक कोशिश भी सफल रहती है तो इससे निजीकरण का रास्ता खुल जाएगा। करों में कटौती भी खपत बढ़ाने की सरकार की मंशा का संकेत है।'

सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.5 फीसदी रखने और वित्त वर्ष 2021 में शुद्ध सरकारी उधारी के 5.36 लाख करोड़ रुपये रहने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है जिससे बॉन्ड प्रतिफल और भारतीय उद्योग जगत के लिए फंड की लागत काबू में रहेगी।

एचडीएफसी बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री अभीक बरुआ ने कहा, 'बॉन्ड बाजार के लिए उधारी के आंकड़े बाजार की उम्मीदें के अनुरूप है और इसमें हाल फिलहाल प्रतिफल पर कोई खास दौव आने की उम्मीद नहीं है।'

विदेशी निवेशकों को प्रोत्साहन

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

बजट में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। डीडीटी में राहत से भी बढ़ेगा मनोबल

एफपीआई के लिए भारत में ब्याज से होने वाली कमाई पर कर छूट की अवधि बढ़ा दी गई है

आम बजट में विदेशी निवेशकों को रिझाने के लिए कुछ उपायों की घोषणा की गई है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए लाभांश पर कर की दर 20 फीसदी होगी। कुछ देशों के साथ भारत की संधियों में लाभांश पर कर की कम दर का प्रावधान है और अगर एफपीआई इसके पात्र हैं तो उन्हें इसका फायदा होगा।

ध्रुव एडवाइजर्स में पार्टनर सौमिल शाह ने कहा, 'विदेशी शेयरधारक कर संधि के तहत कमतर विदहोल्डिंग टैक्स का लाभ ले सकते हैं, बशर्ते वे इसकी मुख्य उद्देश्य पूरा करते हों।' नांगिया एंडरसन के पार्टनर सुनील गिडवानी ने कहा, 'लाभांश वितरण कर (डीडीटी) की जगह अब शेयरधारक पर कर लगाया जा रहा है। ऐसे में कर संधि की दर विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध रहेगी। उदाहरण के लिए सिंगापुर और मॉरीशस के साथ कर संधियों के मुताबिक लाभांश पर कर की दर 5 फीसदी है, बशर्ते भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी चुकता शेयर पूंजी की कम से कम 10 से 25 फीसदी हो। अन्यथा यह 15 फीसदी है। अब ये दरें लागू होंगी।'

अलबत्ता एफपीआई भारत में चुकाए गए कर के लिए अपने देश में क्रेडिट का दावा कर सकता है और संधि के तहत कम दर का दावा नहीं कर सकते हैं, अगर उनके देश में लाभांश पर कर की दर 20 फीसदी के बराबर या उससे अधिक है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया में एमऐंडए टैक्स के लीडर हितेन कोटक के मुताबिक डीडीटी भारतीय कंपनियों पर एक अतिरिक्त बोझ था और इससे विदेशी कंपनियों को भारतीय परिचालन कंपनियों में होल्डिंग कंपनियों या अपने निवेश का अधिग्रहण करना महंगा पड़ता है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) को भारत में ब्याज पर होने वाली कमाई पर कर में मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। एफपीआई को भारतीय कंपनियों और सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा रुपये में जारी बॉन्ड पर ब्याज मिलता है। अभी उन्हें 5 फीसदी की दर से कर देना पड़ता है। अब यह व्यवस्था 30 जून, 2023 तक बरकरार रहेगी।

वर्ष 2013 में रुपये के लड़खड़ाने के बाद सरकार ने एफपीआई के लिए कर की दर में कटौती की थी ताकि विदेशी निवेश को बाहर जाने से रोका जा सके। यह 31 मई, 2015 तक भुगतान किए गए ब्याज पर लागू किया गया था। 2014 में ऋण श्रेणी में रिकॉर्ड एफपीआई प्रवाह से सरकार ने दो बार रियायती दर की अवधि बढ़ाई थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि कर की कम दर के कारण भारतीय ऋण बाजार विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। रियायती दर से सरकार और कंपनियों को उधारी लागत कम करने में मदद मिली है।

बजट में विदेशों में भारत केंद्रित फंडों का प्रबंधन कर रहे फंड मैनेजरों के लिए भी नियमों में कुछ ढील दी है ताकि वे फंड को भारत ला सकें। ऑफशोर फंड अब स्थापना के एक साल के भीतर 100 करोड़ रुपये का कोष हासिल कर सकते हैं। पहले यह अवधि छह महीने थी।

प्रतिक्रिया

बजट भाषण काफी लंबा था लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें खपत को बढ़ावा देने के ज्यादा उपाय किए गए हैं। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बजट में कुछ और ठोस उपायों की उम्मीद थी।

आदि गोदरेज
चेयरमैन, गोदरेज समूह

बजट में कृषि और बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे निवेश चक्र और रोजगार में सुधार होगा। ग्रामीण भारत में आय बढ़ाने का वादा किया गया है जिससे उपभोग मांग में वृद्धि होगी।

संजीव पुरी
सीएमडी, आईटीसी

बजट में निजी क्षेत्र के लिए निवेश बढ़ाने और तेजी से विकास करने का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। परिवहन ढांचा परियोजना पर 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे वाहन उद्योग को मदद मिलेगी।

केनिची आयुकावा
एमडी एवं सीईओ, मारुति सुजूकी इंडिया

बजट प्रभाव

कम आय वाले करदाताओं को कर में छूट मिलने से उपभोग मांग में इजाफा होने की उम्मीद है, जो अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए जरूरी कदम है

बजट में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की ठोस बुनियाद रखी गई है। उभरती वैश्विक प्रौद्योगिकी ज्ञान के साथ-साथ समावेशी विकास पर जोर दिया गया है।

सुनील भारती मित्तल, चेयरमैन, भारती एंटरप्राइजेज

वित्त मंत्री ने उद्योगों को किया निराश

कंपनी जगत

उद्योग जगत बजट में खपत को बढ़ाने के लिए साहसिक उपायों की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके हाथ निराशा लगी

उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज लोकसभा में पेश वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। गोदरेज समूह के चेयरमैन आदि गोदरेज जैसे दिग्गज उद्योगपतियों ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बजट में बड़ी घोषणाएं नहीं किए जाने पर निराशा व्यक्त की। उनका कहना है कि इससे लंबे समय तक खपत में मंदी का दौर रहेगा।

गोदरेज ने कहा, 'बजट में ज्यादा कुछ नहीं है। वित्त मंत्री ने केवल कुछ मामूली बदलाव किए हैं। इसके पीछे सोच एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने की रही है। इससे किसका भला होगा? अर्थव्यवस्था आज बुरी स्थिति में है। हमें साहसिक कदमों की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है।'

बाजार शोधकर्ता नीलसन ने पिछले सप्ताह कहा था कि घरेलू एफएमसीजी बाजार अक्टूबर-दिसंबर 2019 में छह तिमाहियों के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और जनवरी-मार्च, 2020 तिमाही में इसमें सुधार की उम्मीद है। लेकिन कुछ कंपनियों के अधिकारी इससे सहमत नहीं हैं। मुंबई की एक शीर्ष एफएमसीजी कंपनी के प्रमुख ने कहा कि यह बजट कई मायनों में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का अंतिम उपाय था। उन्होंने कहा, 'आईएमएफ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ हफ्ते पहले क्या कहा था। उसने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 5 फीसदी से नीचे जा चुकी है और इससे मौजूदा वित्त वर्ष में दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। मुझे लगता है कि बाजार में फिर से ग्राहकों को लाने के लिए तत्काल कुछ अहम उपाय किए जाने की जरूरत थी। बुरे वक्त में बाजार की धारणा को मजबूत करना बेहद जरूरी है।'

खपत बढ़ाने के लिए बजट में आय कर दरों में उल्लेखनीय बदलाव की दरकार थी। लेकिन वित्त मंत्री ने केवल 15 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कर की दरों में कमी की है जबकि 5 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई कर नही लगेगा। लेकिन इसमें भी एक पेच है। अगर करदाता नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है तो उसे कोई छूट नहीं मिलेगी।

मारुति सूजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने स्वीकार किया कि 15 लाख रुपये से अधिक कमाई वाले करदाताओं को कर में छूट नहीं देना निराशाजनक है। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि कम आय वाले करदाताओं के पास अब खर्च करने के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे होंगे।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी ने कहा कि कर कटौती से वास्तव में खपत को बढ़ावा मिलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात है। उन्होंने कहा, 'सरकार ने बजट में ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे, उद्यमिता और वित्तीय क्षेत्र पर जोर दिया है। अब यह देखना होगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र कितना आगे जाता है।'

सीतारमण ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साथ ही कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। इनमें सिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज शामिल है।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए 16 सूत्री योजना भी पेश की। इसमें राज्यों को आदर्श कृषि कानूनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों में व्यापक उपाय किए जाएंगे।

फोटोः दलीप कुमार

नीलसन ने पिछले सप्ताह कहा था कि घरेलू एफएमसीजी बाजार न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है और जनवरी-मार्च तिमाही में सुधार की उम्मीद है

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा, 'इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया गया है कि कृषि क्षेत्र में पैसे कहां खर्च होंगे। यह बजट केवल घोषणाओं का नहीं है बल्कि इसमें कृषि क्षेत्र में ढांचागत बदलाव के ठोस उपाय किए गए हैं। इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आपको एकदम कोई बदलाव नहीं दिखेगा। बजट से तत्काल कुछ नहीं बदल सकता है लेकिन इससे दीर्घकालिक ढांचागत बदलाव देखने को मिलेंगे।' गोयनका को उम्मीद है कि रबी की फसल अच्छी होने के कारण आने वाले महीनों में ट्रैक्टरों की मांग बढ़ेगी। साथ ही रबी फसल से हुई अच्छी कमाई से इससे खरीफ की बुआई में भी मदद मिलेगी।

जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एक्सआईएम) में प्रोफेसर एचके प्रधान ने कहा कि सरकार ने मध्य वर्ग को कठिन विकल्प दिया है। लाभांश वितरण कर हटाने से निवेशकों पर कर बोझ किस तरह कम होगा, यह देखना होगा क्योंकि उन्हें आय कर के रूप में ज्यादा राशि चुकानी पड़ सकती है। प्रधान ने कहा कि बजट में मांग में कमी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है और ग्रामीण खपत को पटरी पर लाने के लिए किसी उपाय की घोषणा नहीं की गई है। खपत में कमी को दूर करने के लिए यह बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्री ने आर्थिक विकास को पटरी पर लाने की चुनौतियां बाजार पर छोड़ दी हैं। उच्च ब्याज दरों, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए वित्त पोषण की अस्पष्टता और बैंकों से ऋण प्रवाह को बढ़ाने के विशेष उपायों के अभाव में आर्थिक विकास में अड़चन आएगी।'

(साथ में शैली सेठ मोहिले और अर्णव दत्ता)

खपत नहीं बढ़ेगी जल्द

- बजट उपायों से खपत बढ़ने की उम्मीद नहीं
- लंबे समय तक रह सकती है खपत में मंदी
- अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए चाहिए साहसिक उपाय
- बाजार की धारणा मजबूत करना बेहद जरूरी

दबाव से कराह रहे क्षेत्रों को नहीं मिली बड़ी मदद

संकटग्रस्त क्षेत्र

रियल एस्टेट, वाहन और दूरसंचार जैसे अर्थव्यवस्था के कमजोर पड़ते क्षेत्रों को केंद्रीय बजट ने नहीं दी बहुप्रतीक्षित राहत

रियल एस्टेट, वाहन और दूरसंचार सेवा जैसे क्षेत्र भारी दबाव से गुजर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय बजट में इन क्षेत्रों की समस्याओं पर गौर नहीं किया गया। आयकर दरों में कमी जैसे बाहरी उपायों के अलावा सरकार की तरफ से कोई सीधी मदद नहीं मिलने से ज्यादातर उद्योगपति असंतुष्ट नजर आए।

रियल एस्टेट का ही उदाहरण लें। वित्त वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट में कहा गया है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में 8 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां नहीं बिक पाई हैं और यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में मंदी लाने में काफी हद तक जिम्मेदार है। हालांकि निवेशकों के लिए सस्ते मकान खरीदने में कर प्रोत्साहन हासिल करने की तारीख में बढ़ोतरी के अलावा बजट में मकानों की बिक्री बढ़ाने के लिए अन्य कोई प्रत्यक्ष कदम नहीं उठाया गया।

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि अर्थव्यवस्था भारी मंदी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में वित्त बिक्री बढ़ाने के कारक के रूप में काम करने की वर्ष 2021 के केंद्रीय बजट से उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने कहा, 'हालांकि यह बजट उद्योग की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाया, जिसमें वृद्धि को बढ़ाने के लिए कोई प्रमुख घोषणा नहीं की गई। छूट को खत्म करके आयकर की दरों को कम करने से खपत में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं होगी। जहां तक रियल एस्टेट क्षेत्र का सवाल है, यह उद्योग उम्मीद कर रहा था कि सरकार मकानों की मांग बढ़ाने के उपाय लेकर आएगी।' इक्रा लिमिटेड के समूह प्रमुख और वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुभम जैन ने कहा, 'क्षेत्र के लिए आवंटन और कटौतियां बढ़ाने से संबंधित बजट के प्रावधानों को लेकर डेवलपर और निवेश समुदाय की उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा नए वैकल्पिक व्यक्तिगत कर ढांचे के तहत आवास ऋणों पर कटौतियां लागू नहीं होने से आवास ऋण लेने के बारे में विचार करने वाले लोग हतोत्साहित होंगे।'

क्रेडाई के अध्यक्ष सतीश मागर ने कहा कि सरकार को रियल एस्टेट क्षेत्र पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन क्षेत्र को ज्यादा नकदी मुहैया कराने और ऋणों का एकबारगी पुनर्गठन जैसी इस क्षेत्र से जुड़ी जरूरतों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा, 'यह बजट उत्साहजनक नहीं है।'

उद्योग के कार्याधिकारियों के मुताबिक सरकार का पूरा जोर किफायती आवासों पर है, जिसमें घर खरीदारों और डेवलपरों के लिए पिछली कर छूटों को एक साल और बढ़ा दिया गया है। बजट में ऐसी प्रॉपर्टी पर पूंजीगत लाभ कर में राहत का प्रस्ताव रखा गया है, जिनकी कीमत सर्किल दरों से 10 फीसदी तक कम है। पहले पांच फीसदी का प्रावधान था।

रियल एस्टेट क्षेत्र में 8 लाख करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां नहीं बिक पाई हैं और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में मंदी लाने में काफी अहम भूमिका है

वाहन क्षेत्र 2019 के मध्य से घटती बिक्री से जूझ रहा है। लेकिन इस उद्योग में मंदी आने के बाद पेश किए जा रहे पहले बजट में इसे मामूली राहत मिली। उद्योग के लॉबी समूह सायम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा, 'उद्योग बजट में कुछ ऐसे प्रत्यक्ष लाभ दिए जाने की उम्मीद कर रहा था, जिनसे मांग को बढ़ाने में मदद मिलती। हमने प्रोत्साहन आधारित स्क्रैप पॉलिसी जैसे कुछ सुझाव दिए थे, जिनके बारे में विचार नहीं किया गया।' हालांकि भारत की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजूकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा कि कार विनिर्माता बजट से बहुत कम उम्मीद कर रहे थे। भार्गव ने कहा, 'उद्योग के लिए सबसे बड़ी जरूरत उत्पादन लागत को घटाना है और साफ शब्दों में कहें तो इसमें मदद करने की केंद्रीय बजट में बहुत कम गुंजाइश थी। जीएसटी परिषद कारों पर जीएसटी की दरों का फैसला लेगी। राज्यों को बिजली और अन्य इनपुट की लागत को घटाने की जरूरत है ताकि उत्पादन लागत को घटाया जा सके और इसका लाभ ग्राहकों को दिया जा सके।'

उन्होंने कहा कि इस कदम से शुरुआती स्तर की कारों के खरीदारों के हाथ में ज्यादा पैसे बचेंगे। शुरुआती स्तर की कारों की बिक्री प्रभावित हुई है। ऋण लागत और नए सुरक्षा फीचर एवं कई राज्यों में सड़क कर में बढ़ोतरी से पिछले एक साल में कारों की कीमतों में 20 फीसदी से अधिक बढ़ोतरी हुई है।

स्टार्टअप के लिए मामूली प्रोत्साहन

डिजिटल-स्टार्टअप

ईसॉप्स कर स्थगन एवं नए सीड फंड की घोषणा, लेकिन गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर में कोई बदलाव नहीं किया गया

वित्त वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में अहम मांगें नहीं माने जाने से स्टार्टअप और निवेशक समुदाय को निराशा हाथ लगी। बजट में केवल देश में उद्यमिता के तंत्र को बढ़ाना देने के लिए रियायतों में इजाफा किया गया।

स्टार्टअप की प्रमुख मांग गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर पूंजीगत लाभ कर की दर को सुसंगत बनाना, कर्मचारी शेयर विकल्प (ईसॉप्स) पर दोहरे कर को खत्म करना और स्रोत पर कर कटौती को खत्म करना थीं, जो पूरी नहीं हुईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में ईसॉप्स पर कर को स्थगित करने, कॉरपोरेट कर में कटौती के लिए पात्र स्टार्टअप की संख्या बढ़ाने और स्टार्टअप के लिए एक नए सीड फंड की स्थापना की घोषणा की।

वेंचर कैपिटल फर्म 3वन4 कैपिटल के सह-संस्थापक और ईसॉप्स पर दोहरे कराधान के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने वाले सिद्धार्थ पई ने कहा, 'सरकार का कदम उतना बड़ा नहीं है, जितनी लोगों ने उम्मीद की थी।' पई ने कहा, 'सरकार ने कर नहीं हटाया, केवल कर के भुगतान को स्थगित किया है।' सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि ईसॉप्स को पांच साल बाद शेयरों में तब्दील करने पर कर का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी पांच साल पहले कंपनी छोड़ता है और शेयरों की बिक्री करता है तो उसे कर चुकाना पड़ेगा।

पूरी नहीं हुई उम्मीद

- सरकार ने ईसॉप्स कर नहीं हटाया, केवल कर के भुगतान को स्थगित किया

इसके अलावा यह रियायत केवल उन स्टार्टअप पर लागू होती है, जिनकी स्थापना 1 अप्रैल 2016 के बाद हुई है और जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी के तहत सरकार द्वारा नियुक्त अंतर-मंत्रालय बोर्ड (आईएमबी) ने मंजूरी दी है। ईसॉप्स स्टार्टअप में प्रतिभाओं को लाने और बनाए रखने का एक साधन है, जिनके पास शुरुआती दिनों में धन की किल्लत होती है। इस समय ईसॉप्स के आवंटियों को दो बार कर चुकाना पड़ता है। पहली बार ईसॉप्स को कंपनी शेयर बदलते समय (वेतन आय) और दूसरी बार शेयर को बेचने पर (पूंजीगत लाभ)।

कॉरपोरेट कर रियायत

सरकार ने कॉरपोरेट कर में रियायत का लाभ पात्र स्टार्टअप को भी देने का प्रस्ताव रखा है। अब 100 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाली स्टार्टअप अपनी स्थापना की 10 साल की अवधि में तीन साल लाभ पर कर में छूट हासिल कर सकती हैं। पहले यह छूट 25 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाली स्टार्टअप को ही मिलती थी और वे इसे सात साल की अवधि में ही हासिल कर सकती थीं।

मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि पांच करोड़ से कम टर्नओवर वाले कारोबारों को अपने खातों का बाहरी अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा एक सीड फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है, जो सीधे स्टार्टअप में निवेश करेगा।

केंद्रीय बजट में क्वांटम प्रौद्योगिकी पर जोर

तकनीकी क्षेत्र

बजट में क्वांटम कंप्यूटिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। अमेरिका और चीन पहले ही इस दिशा में काफी आगे बढ़ चुके हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में पेश 2020-21 के आम बजट में अगले 5 साल में नैशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी ऐंड ऐप्लिकेशंस के गठन के लिए 8,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'क्वांटम टेक्नोलॉजी से कम्प्यूटिंग, कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी के लिए नए अवसर खुल रहे हैं।'

माना जा रहा है कि कि क्वांटम कम्प्यूटिंग के आने से साइबर सिक्योरिटी से लेकर दूरसंचार, वित्त, दवा और विनिर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव होंगे। शोध फर्म सीबी इनसाइट्स के मुताबिक क्वांटम कम्प्यूटर डेस्कटॉप जैसे पुराने कम्प्यूटरों की तुलना में बहुत तेजी से व्यापक और जटिल डेटाबेस को प्रोसेस कर सकते हैं। वे जटिल गणना के समाधान की प्रोसेस की गति तेज करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के मूल सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका और चीन ने क्वांटम कम्प्यूटिंग में अरबों डॉलर का निवेश किया है क्योंकि वे अर्थव्यवस्था और सेना के लिए इस प्रौद्योगिकी के रणनीतिक महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही अरबों डॉलर की क्वांटम कम्प्यूटिंग की बड़ी परियोजना की शुरुआत कर चुके हैं। इसके तहत 2030 तक इस क्षेत्र में कई बड़े लक्ष्य हासिल किए जाने हैं। चीन साथ ही नैशनल लेबोरेटरी फॉर क्वांटम इनफॉरमेशन साइंसेज का निर्माण कर रहा है। 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत सरकार ने क्वांटम इनफॉरमेशन साइंस के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए 1.2 अरब डॉलर का निवेश किया था।

प्रौद्योगिकी कंपनियां साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम कम्प्यूटिंग पर बड़ा दांव लगा रही हैं

देश में क्वांटम साइबर सुरक्षा से जुड़े उत्पाद विकसित करने वाली एकमात्र कंपनी क्यून्यू के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी सुनील गुप्ता ने कहा, 'आज की घोषणा से सरकार ने भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी के नक्शे पर लाने के लिए एक साहसिक और बहुप्रतीक्षित कदम बढ़ाया है।'

उन्होंने कहा कि क्वांटम कम्प्यूटिंग में किए गए प्रयासों से न्यू मटीरियल रिसर्च, अंतरिक्ष अन्वेषण और मशीन लर्निंग ऐप्लिकेशंस जैसे कई क्षेत्रों में फायदा होगा। इस निवेश का तुरंत फायदा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। गुप्ता ने कहा कि क्वांटम कम्प्यूटर का स्याह पक्ष यह है कि यह अधिकांश मौजूदा एनक्रिप्शन स्कीमों को तोड़ सकता है जिससे अहम डेटा और राष्ट्रीय गोपनीयता के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।

गूगल, अलीबाबा, इंटेल, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियां बेहतर साइबर सुरक्षा के लिए पहले से ही क्वांटम कम्प्यूटिंग पर बड़ा दाव लगा रही हैं।

गुप्ता ने कहा कि बजट में आवंटित निवेश का बड़ा हिस्सा देश में रक्षा और अहम बुनियादी क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए क्वांटम नेटवर्क के निर्माण पर खर्च किया जाना चाहिए। इस निवेश के सही इस्तेमाल के लिए भारत को नीतिगत समर्थन की जरूरत है।

बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप क्लेंस्टा इंटरनैशनल के मुख्य कार्यकारी पुनीत गुप्ता ने कहा कि क्वांटम प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति देश में इस बारे में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम होगा। डेटा को नया तेल बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए सरकार जल्दी ही एक नीति लेकर आएगी। एलऐंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निदेशक केशव पांडा ने कहा कि डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे देश में डेटा और डेटा एनालिटिक्स की अहमियत का पता चलता है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक ओंकार राय ने कहा कि डेटा सेंटरों के बारे में नीतिगत पहल से देश के दूरदराज इलाकों में आईटी सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। इससे न केवल डिजिटल अंतर पाटने में मदद मिलेगी बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी क्रांति आएगी। साथ ही इससे इस क्षेत्र में एफडीआई आएगा।

बजट आंकड़ों में

घरेलू सामान पर सीमा शुल्क बढ़ा

सीलिंग और टेबल फैन, कॉफी मशीन, शेवर्स, ग्राइंडर और मिक्सर जैसे विभिन्न घरेलू सामान पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत हुआ। सेल्युलर फोन के लिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एसेंबली पर शुल्क दोगुना कर 20 प्रतिशत किया गया और डिस्पले पैनल तथा टच एसेंबली पर इसे शून्य से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन किट पर शुल्क में वृद्धि

संपूर्ण रूप से तैयार वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया है। यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के सेमी-नॉक्ड डाउन यूनिट पर शुल्क दोगुना कर 30 प्रतिशत और बसों, ट्रकों और दोपिहया के सेमी नॉक्ड यूनिट के लिए इसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 फीसदी किया गया है।

सिगरेट, तंबाकू पर शुल्क में भारी बढ़ोतरी

सिगरेट पर उत्पाद शुल्क में बड़ा इजाफा किया गया है। 65 एमएम से कम के गैर-फिल्टर सिगरेट के लिए उत्पाद शुल्क 90 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति एक हजार किया गया है। वहीं 65 एमएम से अधिक और 70 एमएम तक के फिल्टर वाले सिगरेट पर यह शुल्क 145 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति हजार किया गया है।

जल्द निपटेंगे एफटीए के दावे

मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत लाभ के अनुचित दावों पर अंकुश लगाने के लिए एफटीए के तहत होने वाले आयात की सख्त जांच होगी। इस उद्देश्य के लिए सीमा शुल्क कानून में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।

सेफगार्ड शुल्कों के प्रावधान होंगे मजबूत

संशोधित प्रावधानों से आयात में अनावश्यक तेजी के विनियमन को सुगम बनाने में मदद मिलेगी। रियायती सामान के आयात और इनकी डंपिंग पर नजर रखने वाले प्रावधानों को भी मजबूत बनाया जा रहा है।

सीमा शुल्क छूट की होगी समीक्षा

सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सीमा शुल्क में छूट दी जाती है। समीक्षा के तौर पर, ऐसी कुछ खास रियायतों को वापस लिया जा रहा है।

बजट प्रभाव

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें सार्वजनिक बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली 90,000 करोड़ रुपये की संभावित रकम शामिल है। एलआईसी के अलावा आईडीबीआई बैंक में भी हिस्सेदारी बेचने पर विचार।

"ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री बाजार की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी नहीं उतर पाईं। इससे खुदरा निवेशकों के लिए आगे बाजार में उतार-चढ़ाव का माहौल रह सकता है"

केशव मुरुगेश, ग्लोवल सीईओ, डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज और नैसकॉम के चेयरमैन

विनिवेश का भारी भरकम लक्ष्य

विनिवेश

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य तय किया है

मौजूदा वित्त वर्ष में रणनीतिक बिक्री के मोर्चे पर बहुत ज्यादा काम भले ही न हुआ हो, लेकिन केंद्र सरकार ने अब अगले साल के विनिवेश लक्ष्य में भारी इजाफा किया है। इसका अहम हिस्सा हालांकि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिये भारतीय जीवन बीमा निगम की अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री होगा।

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विनिवेश का लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रुपये तय किया गया है, जिसमें सार्वजनिक बैंकों व वित्तीय संस्थानों से मिलने वाली 90,000 करोड़ रुपये की संभावित रकम शामिल है। एलआईसी के अलावा सरकार आईडीबीआई बैंक में बाकी बची हिस्सेदारी बेचने पर भी विचार कर रही है। वित्त सचिव राजीव कुमार ने बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वित्तीय क्षेत्र के विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपये एलआईसी व आईडीबीआई बैंक से आएंगे। सूचीबद्धता के समय मूल्यांकन पर फैसला लिया जाएगा। बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, स्टॉक एक्सचेंजों पर किसी कंपनी को सूचीबद्ध कराने से उसमें अनुशासन आता है और वित्तीय बाजार तक उसकी पहुंच होती है और खुद का मूल्यांकन भी पता चलता है। यह खुदरा निवेशकों को अब तक सृजित हुई संपत्ति में भागीदारी का मौका देता है। सरकार ने अब आईपीओ के जरिये एलआईसी में अपनी हिस्सेदारी का एक भाग बेचने का प्रस्ताव रखा है।

अगले साल का लक्ष्य हालांकि ज्यादा है जबकि सरकार वित्त वर्ष 2017-18 में 1,00,056.91 करोड़ रुपये जुटा पाई थी। अगले साल के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य हालांकि 2019-20 के संशोधित अनुमान से तीन गुना ज्यादा है। सरकार को उम्मीद है कि 1.05 लाख करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य के मुकाबले 65,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस साल के लिए कुछ पीएसयू की रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री की योजना बनी थी, जो अगले साल पूरी होगी। निवेश व सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) की वेबसाइट के मुताबिक, सरकार को इस साल पीएसयू की हिस्सेदारी बिक्री से अब तक सिर्फ 18,094.59 करोड़ रुपये मिले। इसमें रेल विकास निगम और आईआरसीटीसी के आईपीओ से मिली रकम शामिल है। और कुछ दिन पहले भारत ईटीएफ से सरकार को 21,000 करोड़ रुपये मिले।

सीतारमण ने कहा है कि मार्च 2020 तक उसे विनिवेश से कुल 65,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, लेकिन संभावना यह है कि कम से कम एक बड़ी पीएसयू की बिक्री रणनीतिक निवेशक को करने का काम इस साल पूरा हो जाएगा। यह सरकारी कंपनियों में रणनीतिक हिस्सेदारी की बिक्री पर 17 साल से लगी लगाम को खोल देगा। विनिवेश सचिव टी पांडे ने कहा, बीपीसीएल, कॉनकॉर, शिपिंग कॉरपोरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की हिस्सा बिक्री का काम इस साल पूरा हो जाएगा जबकि कुछ अगले साल होगा। सरकार ने नवंबर में पांच पीएसयू की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी, जिसमें से दो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नीपको की खरीद अन्य पीएसयू एनटीपीसी करेगी। अन्य तीन बीपीसीएल, कॉन्कोर और एससीआई का निजीकरण होगा।

राजग सरकार 20 कंपनियों के निजीकरण की कोशिश कर रही है, जिसका फैसला 2017 में लिया गया था और इनमें एयर इंडिया शामिल है। एयर इंडिया के लिए अभिरुचि पत्र मंगाए जा रहे हैं जबकि पिछली बार किसी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी। पांडे ने कहा, हमने विनिवेश के लिए कई लेनदेन की रूपरेखा तय की है। एयर इंडिया के लिए ईओआई मंगाए जा रहे हैं जबकि बीपीसीएल के लिए ईओआई जल्द ही मंगाए जाएंगे।

सिरिल अमरचंद मंगलदास के पार्टनर एल विश्वनाथन के मुताबिक, आईडीबीआई और एलआईसी की हिस्सेदारी बिक्री और एलआईसी को सूचीबद्ध कराने का प्रस्ताव साहसी कदम है और यह निवेश व लोन पोर्टफोलियो के खुलासे के अलावा बेहतर प्रशासन में सक्षम बनाएगा। साथ ही पारदर्शिता बेहतर होगी और जवाबदेही बढ़ेगी। यह सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार लाएगा और इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल विकास की गतिविधियों में हो पाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 में सरकार को विनिवेश से कुल 65,000 करोड़ रुपये ही मिलने की उम्मीद है

बड़ा लक्ष्य

- एलआईसी के अलावा सरकार आईडीबीआई बैंक में बाकी बची हिस्सेदारी बेचने पर भी विचार कर रही है
- सीतारमण ने कहा, स्टॉक एक्सचेंजों पर किसी कंपनी को सूचीबद्ध कराने से उसमें अनुशासन आता है और वित्तीय बाजार तक उसकी पहुंच होती है
- राजग सरकार 20 कंपनियों के निजीकरण की कोशिश कर रही है, जिसका फैसला 2017 में लिया गया था और इनमें एयर इंडिया शामिल है

सरकार लेगी 8.1 लाख करोड़ रुपये उधार

उधारी

दिसंबर तक छोटी बचत के जरिये सरकार को 1.2 लाख करोड़ रुपये मिले, जो 2019-20 के लक्ष्य 2.4 लाख करोड़ रुपये का आधा है

वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार बाजार से 8.1 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी और मौजूदा वित्त वर्ष में बाजार के अनुमान के उलट अतिरिक्त उधारी की ओर नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसके बजाय छोटी बचत से ज्यादा संसाधन जुटाएगी। बजट दस्तावेज में ये बातें कही गई है। लेकिन बाजार में हर कोई इसे मानने को तैयार नहीं है।

अतिरिक्त उधारी शायद ज्यादा नहीं होगी क्योंकि राजकोषीय घाटा पहले के 3.3 फीसदी (जीडीपी) लक्ष्य के मुकाबले बढ़कर 2019-20 के लिए 3.8 फीसदी पर पहुंच गया है। अगले साल के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.5 फीसदी अनुमानित है।

अगले साल के लिए सकल उधारी का आंकड़ा बाजार अनुमान के मुताबिक है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद कर रहे थे कि सरकार मौजूदा वित्त वर्ष के लिए बॉन्ड बाजार से 30 से 50,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेगी। इसके बजाय सरकार ने कहा कि वह मौजूदा वित्त वर्ष में छोटी बचत के जरिये 2.4 लाख करोड़ रुपये का संसाधन जुटा लेगी, जो जुलाई के बजट में 1.3 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था। 2020-21 के लिए भी सरकार छोटी बचत के जरिये 2.4 लाख करोड़ रुपये का संसाधन जुटाने की उम्मीद कर रही है।

बॉन्ड बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए छोटी बचत के जरिए संसाधन का लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है और अतिरिक्त उधारी का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।

मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले दिसंबर तक छोटी बचत से सिर्फ 1.21 लाख करोड़ रुपये मिले हैं और यह जानकारी महालेखा नियंत्रक के आंकड़ों से मिली। सरकार को उम्मीद है कि बाकी बचे तीन महीने में वह छोटी बचत से बाकी 1.19 लाख करोड़ रुपये जुटा लेगी। बॉन्ड निवेशक को भरोसा नहीं है कि इसे हासिल किया जा सकता है।

कुल मिलाकर 2019-20 में बाजार से शुद्ध उधारी 4.99 लाख करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 5.36 लाख करोड़ रुपये होगी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा, सरकारी बॉन्डों की कुछ निश्चित श्रेणी देसी निवेशकों के लिए उपलब्ध रहने के अलावा पूरी तरह से एनआरआई के लिए खोली जाएगी।

बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच के ट्रेजरी प्रमुख जयेश मेहता ने कहा, वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने से पहले यह अग्रगामी कदम हो सकता है। चीन जैसे कुछ देशों ने वास्तव ने अपने पूरे बॉन्ड बाजार को विदेशियों के लिए नहीं खोला है, लेकिन वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल करने के लिए कुछ निश्चित बॉन्ड को पूरी छूट दी है।

मेहता के मुताबिक, बॉन्ड बाजार के लिए यह बजट सकारात्मक है और सोमवार को प्रतिफल में 5-7 आधार अंकों की गिरावट आ सकती है।

कुल मिलाकर 2019-20 में बाजार से शुद्ध उधारी 4.99 लाख करोड़ रुपये और 2020-21 में 5.36 लाख करोड़ रुपये होगी

सरकार ने कहा कि वह वित्तीय अनुबंध के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएगी ताकि क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में भरोसा पैदा हो। साथ ही सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड में निवेश की सीमा 9 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दी।

मेहता ने कहा, वित्तीय अनुबंध के लिए औपचारिक कदम शुरू करना अच्छा कदम है, लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई के निवेश की सीमा बढ़ाने का फायदा तत्काल नहीं दिखेगा क्योंकि मौजूदा निवेश सीमा का ज्यादातर समय पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है।

ग्लोबल मार्केट्स के ग्रुप हेड बी प्रसन्ना के मुताबिक, कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई के निवेश की सीमा में इजाफा और सॉवरिन वेल्थ फंड के लिए कर मुक्त प्रोत्साहन सकारात्मक कदम है।

छूट का दावा न करने पर कम आय कर की पेशकश वाला कदम धीरे-धीरे बॉन्ड बाजार को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इससे बीमा कंपनियों की बिक्री प्रभावित होगी। बीमा कंपनियां बैंकों के बाद बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार है।

बॉन्ड डीलरों ने कहा, अगले साल के लिए बॉन्ड बाजार बेहतर है, जिसमें 2.7 लाख करोड़ रुपये स्विच शामिल है। स्विच लेनदेन में सरकार लंबी अवधि का बॉन्ड अल्पावधि में परिपक्व होने वाले बॉन्ड के बदले देती है।

अर्थव्यवस्था को राजकोषीय उपायों से मिलेगा सहारा

राजकोषीय घाटा

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.8 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान जाहिर किया है

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्तीय सुदृढीकरण पर एक पैनल बनाने की घोषणा की है। इससे उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को अपनी आगामी नीति के संकेत भी दे दिए हैं।

सीतारमण ने पूर्व अफसरशाह एनके सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति द्वारा दिए गए एस्केप क्लॉज का इस्तेमाल किया है ताकि चक्रीय-रोधी उपायों का अधिकतम फायदा उठाया जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में से प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा अनुमान में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने के बाद मौद्रिक नीति समिति लगातार दूसरी बार नीतिगत दरों में यथास्थिति बरकरार रख सकती है।

इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि नीतिगत दरों के मोर्चे पर आरबीआई फिलहाल यथास्थिति बरकरार रख सकता है और इसके लिए उसे बजट 2020-21 से राहत मिली है। आमतौर पर राजकोषीय घाटे में वृद्धि का संबंध महंगाई दर में तेजी से होता है। आरबीआई 4 फरवरी को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस पर जरूर गौर करेगी।

अदिति ने कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर सितंबर तक करीब 4 फीसदी रहने का अनुमान है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर दिसंबर में 7.35 फीसदी पर पांच वर्षों की ऊंचाई पर पहुंच गई थी। जबकि केंद्रीय बैंक ने इसे 2 से 6 फीसदी के दायरे में रहने का अनुमान जाहिर किया था। महंगाई दर को खाद्य वस्तुओं की कीमतों से रफ्तार मिली। खाद्य महंगाई दर दिसंबर में 14.12 फीसदी पर लगातार दूसरे महीने दो अंकों में दर्ज की गई थी।

मौद्रिक नीति समिति ने अपनी पिछली बैठक में कहा था कि बजट से वृद्धि को रफ्तार देने के लिए सरकार उपायों का बेहतर संकेत मिलेगा और इसलिए ऐसा लगता है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2020 के लिए 3.8 फीसदी राजकोषीय घाटे का अनुमान जाहिर किया था जबकि बजटीय अनुमान 3.3 फीसदी और वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.5 फीसदी था। एफआरबीएम ऐक्ट के तहत पत्रों में इसे 3 फीसदी दर्ज किया गया था।

सरकार को वर्ष 2019-20 के लिए बजटीय अनुमान के मुकाबले अपने व्यय में 87,757 करोड़ रुपये की कटौती करनी पड़ी क्योंकि कर राजस्व घटकर करीब 3 लाख करोड़ रुपये रह गयाऔर विनिवेश प्राप्तियां करीब 35,000 करोड़ रुपये दर्ज की गईं। राजस्व में कमी के कुछ हिस्से की भरपाई 32,000 करोड़ रुपये के गैर-कर राजस्व के जरिये किया गया। केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए जाने से भी इसमें मदद मिली।

खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी ने कहा, 'अप्रत्याशित राजकोषीय जटिलताओं के कारण 0.5 फीसदी का अंतर उचित ही लगता है। कर तेजी में सुधार होने से सुदृढीकरण की राह आसान होगी।' यह मोदी सरकार के अब तक के सात बजट में दिखने वाला राजकोषीय घाटे में सबसे अधिक वृद्धि है।

सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी पर बरकरार रखने में विफल रही। मूल रूप से वर्ष 2007-08 के लिए 3 फीसदी का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अगले साल उसे हटा दिया गया। हालांकि 2008-09 में वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव दिखा जिससे सरकार को 1.8 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज देना पड़ा था। उससे राजकोषीय घाटा बढ़कर 6 फीसदी तक पहुंच गया जबकि बजटीय अनुमान में इसे 2.5 फीसदी रखा गया था। उसके बाद कई बार 3 फीसदी का लक्ष्य रखा गया लेकिन उसे कभी हासिल नहीं किया जा सका।

रिजर्व बैंक को संकेत

- राजकोषीय घाटा अनुमान में 0.5 फीसदी की बढ़ोतरी किए जाने के बाद मौद्रिक नीति समिति लगातार दूसरी बार नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रख सकती है
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर सितंबर तक करीब 4 फीसदी रहने का अनुमान
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर दिसंबर में 7.35 फीसदी पर पांच वर्षों की ऊंचाई पर पहुंच गई थी
- राजस्व में कमी के कुछ हिस्से की भरपाई 32,000 करोड़ रुपये के गैर-कर राजस्व के जरिये किया गया

वित्तीय क्षेत्र के लिए मजबूती

एलआईसी

एलआईसी को आईपीओ के जरिये सूचीबद्ध करना और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री सरकार के प्रमुख एजेंडे में

नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने और खुद के लिए रकम जुटाने के महत्त्व को महसूस करते हुए सरकार ने आज वित्तीय क्षेत्र के लिए कई उपायों की घोषणा की। इसी क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने की भी योजना बनाई गई है। साथ ही, बैंक जमाकर्ताओं के लिए बीमा की रकम को 1 लाख रुपये से पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार ने अब आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। एलआईसी में भारत सरकार का 100 फीसदी स्वामित्व है जिसे उसकी पॉलिसियों पर सॉवरिन गारंटी का संकेत माना जाता है।

केंद्रीय वित्त सचिव राजीव कुमार ने बजट के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विनिवेश लक्ष्य को काफी हद तक एलआईसी और आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी बिक्री के जरिये पूरा किया जाएगा। अब तक जीवन बीमा क्षेत्र में तीन सूचीबद्ध कंपनियां- एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस- और तीन गैर-जीवन बीमा कंपनियां हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की विश्लेषक काजल गांधी ने कहा कि एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते एलआईसी के मूल्यांकन में निजी कंपनियों के मुकाबले अंतर दिख सकता है। यहां तक कि उसकी 25 से 30 फीसदी प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों पर भी मूल्यांकन करीब 8 से 10 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। जबकि एकमुश्त 10 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री बाजार के लिए कठिन होगा और सरकार इसे काफी हद तक करने की कोशिश कर सकती है।

अश्विन पारीख एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन पारीख ने कहा कि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार एलआईसी की योजनाओं के लिए सॉवरिन गारंटी जारी रखेगी। यदि वह सॉवरिन गारंटी को बरकरार रखती है तो प्रशासन पर सवाल उठ सकते हैं। जबकि सूचीबद्ध होने के साथ ही सरकार विभिन्न संगठनों का वित्त पोषण नहीं कर सकती है जैसार एलआईसी अब तक करती रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से प्रशासन संबंधी जरूरतों का उल्लंघन होगा।

एलआईसी को सूचीबद्ध कराने की बात पिछले 10 वर्षों से चल रही है। इसकी शुरुआत 2005 में एलआईसी के बोर्ड के जरिये की गई थी। उस समय सरकार चिंतित थी क्योंकि एलआईसी ने कई गारंटी वाली योजनाएं जारी की थी। उस दौरान एलआईसी की पूंजी 5 करोड़ रुपये थी और सरकार ने स्पष्ट किया था कि एआईसी की पॉलिसियों की सभी देनदारी एक सॉवरिन गारंटी होगी। पारीख ने कहा कि फिलहाल एलआईसी के पास 200 करोड़ रुपये की पूंजी है। सरकार सॉल्वेंसी अनुपात में सुधार के लिए बीमा कंपनियों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 6,950 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश भी करेगी। साथ ही वह नियामकीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) को बरकरार भी रखेगी। सरकार तीन सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए कदम पहले ही उठा चुकी है।

सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते एलआईसी के मूल्यांकन में निजी कंपनियों के मुकाबले अंतर दिख सकता है

मेरा बजट

संजीव कपूर
प्रसिद्ध शेफ

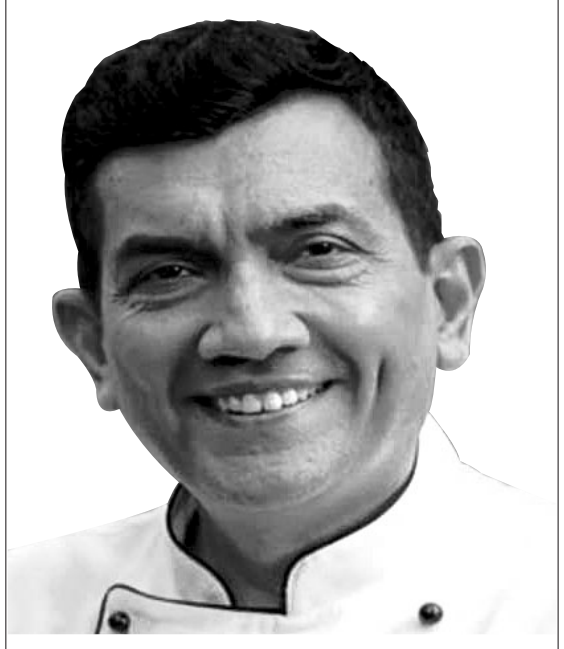

अर्थव्यवस्था को समस्याओं से बाहर निकाला गया ?

चाहे 'एस्पिरेशनल इंडिया' हो अथवा 'केयरिंग सोसाइटी' का बढ़ता चलन, हमने इन विषयों को भारत के बाहर देखा है और यह हमेशा अभिशाप रहेगा। और यह सब लोकलुभावन होने को टालने के लिए बहुत आसान है। मैं समझता हूं कि अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश के साथ इन चीजों के लिए वित्त पोषण एक बड़ी बात है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे यह देखकर खुशी होती है कि लोगों को खुश करने के लिए धन का व्यय नहीं किया जा रहा है।

क्या यह एक लोकलुभावन बजट है ?

वित्त मंत्री ने सब को खुश करने वाला लोकलुभावन बजट पेश नहीं किया है जो मुझे वास्तव में पसंद है। उन्होंने सख्त निर्णय लिए हैं।

क्या इससे अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी ?

सरकार का मानना है कि बुनियादी ढांचा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करने से रोजगार का नवीनीकरण होगा और उपभोक्ता खर्च में तेजी आएगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग इसे किस प्रकार स्वीकार करते हैं। कभी-कभी आपको दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी होती है लेकिन डॉक्टर आपको ठीक बताते हैं। वास्तव में आप बेहतर होने लगते हैं।

बजट की सबसे अच्छी बात क्या रही ?

मुझे खुशी है कि बजट को अब गंभीरता से देखा जा रहा है।

बजट प्रभाव

बजट में 2020-21 में सीमा शुल्क संग्रह में 10.4 फीसदी का इजाफा होने का अनुमान जताया गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 6.1 फीसदी है

"बाजार की उम्मीदों का आंशिक हिस्सा ही पूरा हो पाया। इससे अल्पावधि में खुदरा निवेशकों के लिए बाजार में उतार चढ़ाव रह सकता है"

मोतीलाल ओसवाल, एमडी व सीईओ, मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज

मंदी के समाधान के लिए उठाए गए पर्याप्त कदम ?

आर्थिक मंदी

आयकर में कटौती वेतनभोगी को खर्च की प्राथमिकता पर दोबारा विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है

आम बजट 2020 ऐसे समय में पेश किया गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था भारी आर्थिक मंदी का सामना कर रही है। हर मोर्चे के संकेतक मसलन उपभोग, विनेश और निर्यात एक दशक में सबसे कमजोर नजर आ रहे हैं।

व्यापक स्तर पर बजट के अलावा पहले से उठाए गए कदम हर मोर्चे पर समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कदम आयकर में कटौती से उपभोग में मजबूती आएगी और कंपनी कर में कटौती निवेश का समाधान निकालेगा। हालांकि इन कोशिशों की कुछ सीमाएं भी हैं, जिसके लिए जब तक पूरक कदम नहीं उठाए जाएंगे, वह इच्छित नतीजे नहीं दे पाएगा।

उपभोग की बात करें (अर्थव्यवस्था में जिसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है) तो यह जीडीपी का करीब 60 फीसदी है। वित्त मंत्री ने आयकर में कटौती की और नया स्लैब लागू किया, जो वैयक्तिक करदाताओं को 40,000 करोड़ रुपये की राहत देगा।

यह वेतनभोगी को खर्च की प्राथमिकता पर दोबारा विचार करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और आय में नरमी के दौरान रुके हुए फैसले दोबारा ले सकता है, खास तौर से वाहन व टिकाऊ उपभोक्ता के मामले में। साथ ही कर कटौती से उपभोग में तत्काल मजबूती ला देगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह हर आयु वर्ग में बदलाव लाएगा। डेलॉयट की पार्टनर नीरू आहुजा ने कहा, नई पीढ़ी को हालांकि फायदा होगा और वे उपभोग पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग सामान्य तौर पर इससे दूर रहेंगे।

नई पीढ़ी शायद कम छूट का दावा कर सकता है। ऐसे में कर कटौती से उपभोग में इजाफे में मदद मिल सकती है, खास तौर से युवाओं के उपभोग वाली वस्तुओं व सेवाओं में।

अग्रिम अनुमान के मुताबिक, उपभोक्ता खर्च साल 2019-20 में कई साल के निचले स्तर 5 फीसदी पर आ गया। लेकिन चिंता की बात है कि सीमा शुल्क में बढ़ोतरी से उपभोग के क्षेत्र पर असर होगा। बजट के मुताबिक, करीब 400 वस्तुओं पर आयात शुल्क में इजाफा किया गया है और ज्यादातर बढ़ोतरी उपभोक्ता सामान पर हुई है।

शुल्क में बढ़ोतरी की अहम वजह मेक इन इंडिया है लेकिन उपभोग में मजबूती के लिहाज से इसका असर विपरीत दिशा में जाएगा। इस साल आयात आठ फीसदी घटा है, जो एक दशक की सबसे तेज गिरावट है।

तक्षशिला इंस्टिट्यूट में अर्थशास्त्र के शिक्षक अविनाश त्रिपाठी ने कहा, कर कटौती का असर अनिश्चित नजर आ रहा है। उन्होंने कहा, बजट के दो मकसद हैं। पहला, व्यक्ति की जेब में रकम डालना। दूसरा, कराधान व्यवस्था के सरलीकरण के लिए अनुपालन की लागत घटाना, भ्रम कम करना और अनिश्चितता दूर करना। पहली नजर में कोई मकसद हासिल नहीं हुआ और इसका शुद्ध असर अस्पष्ट है।

निवेश के लिहाज से पूंजीगत खर्च 18 फीसदी बढ़ाकर 4.1 लाख करोड़ रुपये किया गया है। सड़क व रेलवे पर खर्च बढ़ा है या स्थिर रखा गया है ताकि पूंजीगत खर्च में इजाफा हो। यह निजी कंपनियों को नई परियोजना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

वाहन क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो रिकॉर्ड मंदी से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में बिक्री, नए संयंत्रों और निवेश में लगातार गिरावट जारी रहेगी। देश में वाहन कंपनियों के शीर्ष संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) को बजट से और ज्यादा की उम्मीद थी। सायम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा कि लगता नहीं है कि प्रोत्साहन आधारित वाहन निपटान योजना, डीजल बसों की खरीद के लिए आंवटन और लिथेनियम-आयन बैटरियों के लिए शून्य सीमा शुल्क की हमारी मांग पर ध्यान दिया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के कदम से नई पीढ़ी को हालांकि फायदा होगा और वे उपभोग पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग सामान्य तौर पर इससे दूर रहेंगे

सरकार के कदम

- आयकर में कटौती की और नया स्लैब लागू किया, जो वैयक्तिक करदाताओं को 40,000 करोड़ रुपये की राहत देगा
- निवेश के लिहाज से पूंजीगत खर्च 18 फीसदी बढ़ाकर 4.1 लाख करोड़ रुपये किया गया
- सड़क व रेलवे पर खर्च बढ़ा है या स्थिर रखा गया
- वाहन क्षेत्र में बिक्री, नए संयंत्रों और निवेश में लगातार गिरावट जारी रह सकती है

सीमा शुल्कों में इजाफा, सितंबर में शुल्क में होगी और वृद्धि

कर का बोझ

खिलौनों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फुटवियर सहित विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क में इजाफा करने की घोषणा

घरेलू उद्योग को समर्थन देने, गैर-जरूरी आयातों में कमी लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में खिलौनों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामानों और फुटवियर सहित विभिन्न उत्पादों पर सीमा शुल्क में इजाफा करने की घोषणा की। इसके अलावा चिकित्सा उपकरणों पर एक स्वास्थ्य उपकर की भी घोषणा की गई जिससे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा।

आयात शुल्क नियम में भी बदलाव करने का प्रस्ताव दिया गया है जिससे सरकार को किसी भी सामान के अनियंत्रित आयात पर रोक लगाने के लिए सशक्त बनाएगी। अनियंत्रित आयात से देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है। इससे पहले यह निषेध सोना और चांदी के आयात तक सीमित था।

सीतारमण ने कहा, 'मेक इन इंडिया की हमारी नीति का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। भारत अब विश्वस्तरीय

सामानों का निर्माण कर रहा है और ऐसे सामानों का निर्यात कर रहा है। इस उद्देश्य से कुछ उत्पादों और कच्चे मालों पर सीमा शुल्क में कमी की जा रही है जबकि घरेलू स्तर पर बनने वाले कुछ सामानों पर इसे संशोधित कर बढ़ाया जा रहा है।'

फुटवियर पर सीमा शुल्क या आयात शुल्क को 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किया जा रहा है जबकि खिलौनों के मामले में यह बढ़ोतरी 20 फीसदी से 60 फीसदी की जा रही है।

इसके साथ ही सरकार अगले वित्त वर्ष के सितंबर में कारोबारी सुगमता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क कानून और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के साथ ही सीमा शुल्क छूटों में कटौती करेगी।

निर्मला सीतारमण ने कहा, 'समय समय पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्कों से छूट दी जाती रही है। हालांकि, इनमें से बहुत से शुल्कों की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है या फिर ये पुराने हो चुके हैं। समीक्षा करने के बाद इनमें से कुछ छूटों को वापस लिया जा रहा है। बचे हुए सीमा शुल्क छूटों का सितंबर, 2020 में व्यापक स्तर पर समीक्षा की जाएगी और उनकी प्रासंगिकता पर विचार किया जाएगा।' उन्होंने इन समीक्षाओं के लिए लोगों से सुझाव मांगे।

वित्त वर्ष 2019 में सीमा शुल्क के संग्रह में 30,900 करोड़ रुपये की कमी देखी गई। बजट में 2020-21 में सीमा शुल्क संग्रह में 10.4 फीसदी का इजाफा होने का अनुमान जताया गया है जो मौजूदा वित्त वर्ष में 6.1 फीसदी है।

बजट से इतर उधारी से सब्सिडी दिखी कम

सब्सिडी का पेच

2020-21 के बजट अनुमान में सब्सिडी पर खर्च 2,27,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है

अर्थव्यवस्था में राजकोषीय चिंताएं 2020 के बजट में अनुमान से कहीं ज्यादा नजर आ रही हैं। सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी सहित विभिन्न प्रमुख सब्सिडी के वित्तपोषण के लिए बजट से इतर वित्तपोषण को बहाल नहीं किया है। राजस्व व्यय में तीन क्षेत्र मिलकर अहम घटक बनाते हैं। इन वस्तुओं के मद में व्यय बजट के स्तर 3,01,694 करोड़ रुपये से घटाकर 2019-20 के संशोधित अनुमान में 2,27,255 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

2020-21 के बजट अनुमान में सब्सिडी पर खर्च 2,27,794 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है।

बजट अनुमान की तुलना में वित्त वर्ष 2020 के संशोधित अनुमान में सब्सिडी में कमी की मुख्य वजह भारतीय खाद्य निगम की खाद्य सब्सिडी की जररूरतों का वित्तपोषण करने के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष का इस्तेमाल थी। वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम के तहत पेश आंकड़ों से यह पता चलता है।

बयान में कहा गया है, 'इससे (सब्सिडी) पता चलता है कि वित्त वर्ष 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में इसमें महज 0.2 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है।' बहरहाल अगर 2019-20 के बजट अनुमान से तुलना करें तो संशोधित अनुमान में सब्सिडी में 24 प्रतिशत से ज्यादा की कमी की गई है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर बजट से इतर वित्तपोषण को लेकर सरकार की खिंचाई की है। सीएजी ने इस आधार पर आलोचना की है कि इस तरह की व्यवस्था देनदारी की प्रतिबद्धता (सब्सिडी बकाया व बिल) से इतर या भविष्य की देनदारी पैदा करने वाली है और ब्याज पर भुगतान करने के कारण इससे सब्सिडी की लागत में बढ़ोतरी होती है।

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 2019-20 के संशोधित अनुमान में 1.1 प्रतिशत और 2020-21 के बजट अनुमान में 1 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। वहीं 2019-20 के बजट अनुमान में सब्सिडी जीडीपी का 1.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। 2022-23 में सब्सिडी घटकर जीडीपी का 0.9 प्रतिशत रहने की संभावना है। वित्त मंत्री ने 2020-21 में उर्वरक सब्सिडी पर आवंटन घटाकर 71,309 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमान में 79,998 करोड़ रुपये था। कॉर्पोरेट रेटिंग इक्रा में वाइस प्रेसीडेंट और ग्रुप हेड के रविचंद्रन ने कहा, 'अपर्याप्त सब्सिडी की व्यवस्था करने व सब्सिडी का बकाया बढ़ने से उद्योग की नकदी की स्थिति पर असर पड़ रहा है, जिसका उल्लेख उद्योग जगत बार बार कर रहा है।'

सब्सिडी के बजट में भारी कमी करना उद्योगों के लिए नकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। खासकर ऐसी स्थिति में जब 2 नए यूरिया संयंत्रों से जल्द उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

रविचंद्रन ने कहा, 'सब्सिडी का आवंटन चिंताजनक स्तर तक अपर्याप्त बना हुआ है। ऐसी स्थिति में स्वदेशी यूरिया उत्पादकों की कार्यशील पूंजी की उथारी बढ़ने की उम्मीद है और आने वाले वित्त वर्ष में उनका कार्यशील पूंजी चक्र बिगड़ेगा।'

सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारतीय खाद्य निगम की खाद्य सब्सिडी अग्रिम के रूप में 50,000 करोड़ रुपये कर दी, जो वित्त वर्ष 20 के संशोधित अनुमान में 36,000 करोड़ रुपये था।

सरकार ने सब्सिडी के लिए उधारी का चिंताजनक तरीका अपनाया है

बीएस सूडोकू 3653

			3	7	2			
	8		9				3	2
		1						7
			8			4		
8				4				5
		6			7			
6						9		
3	4				9		6	
			7	6	5			

परिणाम संख्या 3652

2	1	8	6	3	4	5	9	7
9	3	6	8	5	7	1	2	4
4	5	7	1	9	2	6	8	3
7	4	1	5	8	6	2	3	9
6	9	3	2	7	1	8	4	5
5	8	2	3	4	9	7	6	1
1	2	9	7	6	3	4	5	8
3	6	5	4	1	8	9	7	2
8	7	4	9	2	5	3	1	6

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★★☆

मालवहन की नई रणनीति पर काम करेगा रेलवे

रेलवे की माल ढुलाई

भारतीय रेल दूध, मांस और मछली सहित खराब होने वाले खाद्य जिंसों की ढुलाई के लिए किसान रेल चलाई जाएंगी, जिससे राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन बने

भारतीय रेलवे अपने मालवहन रणनीति पर नए सिरे से काम कर रहा है। इसकी वजह है कि केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ ईंधन पर जोर देने के कारण कोयले की ढुलाई कम हो रही है, जिसकी रेल से कुल माल ढुलाई में हिस्सेदारी आधी है।

बजट के बाद आयोजित सम्मेलन में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने कहा, '2019-20 में रेलवे की माल ढुलाई 122.3 करोड़ टन रही, जिसमें से 50 प्रतिशत कोयले और शेष अन्य जिंसों की ढुलाई हुई है।' रेलवे की कुल माल ढुलाई में कोयले की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 21 में घटकर 40 प्रतिशत रहने की संभावना है, जबकि ढुलाई का लक्ष्य 126.5 करोड़ टन रखा गया है।

ताप बिजली उत्पादन में कमी कोयले की ढुलाई कम होने की प्रमुख वजह है। वहीं कोयले की ढुलाई लागत इसलिए भी हुई है कि बिजली कंपनियों ने ढुलाई को तार्किक बनाया है, जिसका असर भी इस जिंस की ढुलाई पर पड़ा है।

यादव ने कहा कि लागत कम करने के लिए ताप बिजली फर्में अनपे ईंधन परिवहन रणनीति पर नए सिरे से काम कर रही हैं, जिसका मतलब यह है कि 'हमें भी अपने माल ढुलाई कारोबार पर फिर से विचार करना होगा'। सितंबर महीने में कोयले के उत्पादन में 21 प्रतिशत की कमी आई है। सितंबर में बिजली उत्पादन में भी 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई है।

उन्होंने बताया कि पिछले 3 वित्त वर्षों से माल ढुलाई और रेलवे का राजस्व बढ़ा है, इसकी प्रमुख वजह सरकार द्वारा उठाए गए कुछ नीतिगत कदम हैं। बहरहाल रेलवे की माल ढुलाई करीब स्थिर रही है और चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में इसमें 0.97 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि खनिज व लौह अयस्क, पेट्रोलियम और कंटेनर क्षेत्रों की ढुलाई में सुधार हुआ है।

रेलवे इस समय ऑटो कंपनियों से कारोबार के लिए भी बात कर रहा है,

पिछले 3 वित्त वर्षों से माल ढुलाई और रेलवे का राजस्व बढ़ा है, इसकी प्रमुख वजह सरकार द्वारा उठाए गए कुछ नीतिगत कदम हैं

खासकर रेल से दोपहिया वाहनों की ढुलाई बढ़ाने पर बात चल रही है। भारतीय रेल दूध, मांस और मछली सहित खराब होने वाले खाद्य जिंसों की ढुलाई के लिए किसान रेल चलाने जा रही है, जिससे बाधारहित राष्ट्रीय कोल्ड सप्लाई चेन बनाई जा सके। यह सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) के माध्यम से किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस और मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटेड कोच होंगे। उन्होंने कहा कि रेल लाइनों के किनारे रेलवे की जमीन पर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने पर भी विचार हो रहा है।

यादव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने ट्रैक से सटे और खाली पड़ी 51,000 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की है, जहां 10 जीडब्ल्यू क्षमता के सौर बिजली संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बहरहाल रेलवे की मौजूदा जरूरत 3.8 जीडब्ल्यू है।

यादव ने कहा, 'इन संयंत्रों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली के इस्तेमाल के लिए हम राज्यों के साथ बात कर रहे हैं।' रेलवे का मकसद है कि 2030 तक पूरे नेटवर्क में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल किया जाए।

बजट को लेकर उद्योग ने कहा कि रेल बजट में सुरक्षा और यात्रियों के अनुभव पर खास ध्यान दिया गया है। बंबार्डियर ट्रांसपोर्टेशन के कंट्री लीडर (इंडिया) राजीव जोएसर ने कहा, 'हमें लगता है कि पीपीपी को आने वाले वर्षों में भारत में गति मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप रोलिंग स्टॉक सहित रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। पीपीपी के माध्यम से किसान रेल चलाने से भारत में कुशल और सुरक्षित रेल व्यवस्था सुनिश्चित होगी।'

बंबार्डियर रेल परिचालन परियोजना पर बहुत नजदीकी से नजर रख रही है और उसने रेल के वरिष्ठ अधिकारियों से परियोजनाओं पर बात की है। जोएसर ने कहा, 'अभी भविष्य की योजना पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि बोली की रूपरेखा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद हम परियोजना का मूल्यांकन करेंगे।'

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 298

आधा-अधूरा प्रयास

आम बजट के निर्माताओं के समक्ष दो चुनौतियां थीं। सरकार की वित्तीय स्थिति दबाव में थी और अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में थी। गलत राजस्व अनुमानों और वृद्धि दर कम होने से वर्ष 2019-20 में सरकार के राजस्व में भारी गिरावट आई। इसी तरह पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2019-20 में जीडीपी वृद्धि दर गिरकर 5 फीसदी रह गई थी। वर्ष 2018-19 के ताजा आंकड़ों को संशोधित कर घटाया गया। यानी 2019-20 में देश की आर्थिक वृद्धि 5.7 फीसदी के साथ पहले से बेहतर स्तर पर नजर आई।

परंतु मंदी के दायरे में कोई अहम बदलाव नहीं नजर आया। सरकार के पास दो विकल्प थे: राजकोषीय शुद्धता की राह पर बने रहना और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना ताकि समय के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार आए या फिर सुधारों को अपनाने के साथ विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं पर व्यय के साथ राजकोषीय प्रोत्साहन देना। परंतु बजट में दोनों विकल्पों को खंगालने का प्रयास किया गया, वह भी आधे-अधूरे मन से। अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्यों पर भरोसा किया गया और कई क्षेत्रों के लिए नाममात्र का व्यय आवंटन किया गया।

राजकोषीय घाटे में 0.5 फीसदी की फिसलन आई और यह 3.8 फीसदी रहा लेकिन अगले वर्ष के लिए 3.5 फीसदी का लक्ष्य तय किया गया। यानी सरकार राजकोषीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन अधिनियम पर टिकी रही जो वर्ष में आधा फीसदी से अधिक गिरावट की इजाजत नहीं देता। इस कानून के तहत 2020-21 तक 3 फीसदी के घाटे का लक्ष्य हासिल करना था लेकिन मौजूदा लक्ष्य भी सवालों के घेरे में हैं। 3.5 फीसदी घाटे का लक्ष्य 2.1 लाख करोड़ रुपये की विनिवेश प्राप्तियों पर निर्भर है। यह चालू वर्ष में हासिल 65,000 करोड़ रुपये से 323 प्रतिशत अधिक है। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी की सूचीबद्धता बड़ा कदम है लेकिन इसके लिए प्रभावी योजना और क्रियान्वयन करना होगा। इसी तरह 2020-21 के लिए 12 फीसदी के सकल कर राजस्व वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए कर उत्प्लावन में 0.5 के मौजूदा स्तर से काफी सुधार कर इसे 1.2 पर लाना होगा।

बजट में एक सराहनीय बात यह है कि वित्त मंत्री ने सरकार की बजट से इतर उधारी के बारे में पारदर्शिता बरतने का प्रयास किया है। कुल 8 फीसदी बढ़ोतरी के साथ इसके 1.86 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। दूसरे शब्दों में इसे मिला दें तो सरकार का वास्तविक बजट घाटा जीडीपी के 4.36 फीसदी का स्तर पार कर जाएगा। बजट में इस उधारी को जिस पारदर्शिता से पेश किया गया है वह अच्छी बात है। इसका असर घाटे के वास्तविक आंकड़े पर भी नजर आना चाहिए। विनिवेश प्राप्तियों की बदौलत सकल कर राजस्व में 12 फीसदी की वृद्धि के अनुमान के बावजूद सरकार व्यय आवंटन को लेकर खामोश नजर आई। कुल व्यय में केवल 13 फीसदी इजाफा किया गया है। प्रमुख सब्सिडी में मामूली बढ़ोतरी और रक्षा आवंटन में केवल 2 फीसदी इजाफा किया गया है। सब्सिडी पर पूरी रोक लगाना कठिन है। यह तभी हो सकता है जब सरकार इस क्षेत्र में बड़े सुधार करे। रक्षा व्यय में मामूली बढ़ोतरी चिंतित करती है क्योंकि देश की रक्षा खरीद बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह पूंजीगत व्यय के लिए बजट सहायता में 18 फीसदी का इजाफा बुनियादी क्षेत्र के लिए अहम मदद है। अगले वर्ष के लिए सरकार का कुल पूंजीगत व्यय 10.84 लाख करोड़ रुपये है। यदि अगले चार वर्ष में 100 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी निवेश लक्ष्य को हासिल करना है तो यह चिंताजनक है क्योंकि इसमें केवल 2.3 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के आवंटन में भी खास इजाफा नहीं किया गया है। यद्यपि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं का पैसा लोगों तक पहुंच रहा है लेकिन वितरण में और सुधार करने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा व्यय पर नियंत्रण रखने की एक वजह यह भी है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के कारण उसके कर राजस्व में केवल 8 फीसदी का मामूली इजाफा हो रहा है। अगले वर्ष राज्यों के कर राजस्व हस्तांतरण में 18 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। यह राज्यों के लिए राहत की बात होगी। सन 2019-20 में राज्यों को होने वाले केंद्रीय करों के हस्तांतरण में काफी कमी आई थी। परंतु यह सवाल उठेगा कि यदि सरकार के पास ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा अन्य परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे तो मध्य वर्ग को कुछ विकल्पों के माध्यम से आय कर दरों में कमी करके 40,000 करोड़ रुपये की अहम कर राहत देने की क्या जरूरत थी? इसके अलावा लाभांश वितरण करने वाली संस्था के बजाय लाभांश पाने वाले के हाथों में लाभांश पर कर के कारण 25,000 करोड़ रुपये की अन्य रियायत भी दी गई। आय कर से रियायतें समाप्त करने का विचार अच्छा है। कॉर्पोरेशन कर देने वालों के लिए ऐसी व्यवस्था लागू है। परंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्यय बढ़ाना वक्त का तकाजा है ताकि मांग का विस्तार हो। बजट की कराधान नीति में 22 नई वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क बढ़ाकर और जटिल एवं गलत रुख अपनाया गया है। इसमें खिलौने, जूते-चप्पल और अखरोट शामिल हैं। बीते कुछ बजट की तरह इस बजट में यह सोचकर सीमा शुल्क बढ़ाने की चूक की गई है कि इससे घरेलू विनिर्माण में सुधार होगा।

अजय मोहंती

अधिक रणनीतिक सोच अपनाने की जरूरत

आम बजट के कथ्य तक लोगों की आसान पहुंच के बीच राजनीतिक संदेश के साथ-साथ आर्थिक नीति निर्माण को लेकर अधिक सुविचारित ढंग से बात रखने की आवश्यकता है। विस्तार से बता रहे हैं **अजय शाह**

वर्ष 2011 से 2020 के बीच वृद्धि का रुझान कमजोर रहा। इस अवधि में कारोबारी चक्र की परिस्थितियां भी कमजोर रहीं। अच्छी बात यह रही कि बजट भाषण में जीडीपी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए व्यापक राजकोषीय विस्तार का आह्वान नहीं किया गया। आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के लिए राज्य और लोगों के बीच के रिश्ते को लेकर कहीं अधिक रणनीतिक विचार प्रक्रिया की आवश्यकता है। इसके अलावा निजी निवेश में सुधार के लिए निजी स्तर पर लोगों की असहजता को दूर करना भी आवश्यक है। बजट भाषण में उल्लिखित उपाय थोड़ी बहुत मदद करेंगे लेकिन वृद्धि में सुधार की आवश्यकता कुछ अलग है।

देश में वृद्धि के रुझान में गिरावट 2011 में आई। इस समय हम कारोबारी चक्र की मंदी के शिकार हैं। आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार से मांग की जा रही है कि दोनों परिस्थितियों में तेजी से बदलाव लाए। कुछ लोगों ने राजकोषीय और मौद्रिक नीति संबंधी प्रतिक्रिया की वकालत की है। इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि हमारा राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.5 फीसदी के आसपास है। प्रोत्साहन देने के लिए इसमें और इजाफा करना होगा। यदि यह जीडीपी के 7.5 फीसदी के बराबर हो जाए तो इससे जीडीपी को 2 फीसदी का प्रोत्साहन मिलेगा।

भारतीय हालात में वृहद नीति के इन उपायों में सीमित क्षमता है। ये केवल कारोबारी परिस्थितियों को प्रभावित कर सकते हैं, वृद्धि के रुझान को नहीं बदल सकते। राजकोषीय नीति की बात करें तो घाटे में और अधिक इजाफा चिंता पैदा करने वाला होगा। अच्छी बात यह है कि बजट भाषण में राजकोषीय घाटे में इजाफा करने जैसी कोई बात शामिल नहीं थी।

हम उच्च वृद्धि रुझान की दिशा में वापसी कैसे कर सकते हैं? समस्या का मूल निजी कॉर्पोरेट निवेश में निहित है। जीडीपी का अधिकांश हिस्सा और ज्यादातर रोजगार निजी क्षेत्र में तैयार हो रहे हैं। जीडीपी में इजाफा और रोजगार में वृद्धि तब होती है जब निजी स्तर पर लोग कारोबार में पूंजी लगाते हैं। सन 1991 से 2011 के बीच हमें तेज वृद्धि हासिल हुई क्योंकि निजी क्षेत्र को निवेश करना और कारोबार खड़ा करना सुरक्षित महसूस हो रहा था। 2011 करीब आते-आते निजी क्षेत्र का मोहभंग होने लगा था।

इसमें बदलाव लाने के लिए राज्य और लोगों के रिश्ते को रणनीतिक नजरिये से देखना होगा। बाजार की विफलता को हल करने के प्रयास के बजाय ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां निजी निवेशक सुरक्षित महसूस करें। बजट भाषण में तमाम उपाय शामिल थे। परंतु उनमें कोई नई नीति नहीं है। भाषण में कोई रणनीतिक तस्वीर पेश करने का प्रयास भी नहीं किया गया। जबकि जुलाई 1991 में तथा कुछ अन्य बजट में हम ऐसा होते देख चुके हैं।

आर्थिक मोर्चे पर एक रणनीति की आवश्यकता है। एक ऐसी निरंतरता भरी नीति जो सरकार के छोटे-छोटे कदमों को आकार दे और सरकार के भविष्य के कदमों के बारे में निजी व्यक्तियों के अनुमान को भी एक स्वरूप प्रदान करे। संचार में कई विकल्प मौजूद हैं लेकिन बजट भाषण इस व्यापक तस्वीर की प्रस्तुति के लिए कहीं बेहतर जगह है। एक छोटे उदाहरण की बात करें तो बजट भाषण में यह उचित ही कहा गया कि देश के दो सबसे बड़े वित्तीय उत्पादों निफ्टी और रुपये की देश से बाहर की गतिविधियों में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। बजट में यह आकांक्षा उचित ही प्रकट की गई कि इस गतिविधि को देश में वापस लाया जाना चाहिए। परंतु नीति निर्माताओं ने गहराई से आवश्यक विश्लेषण नहीं किया।

निजी स्तर पर लोग अपनी कारोबारी गतिविधियों का ऐसा प्रबंधन क्यों करते हैं ताकि निफ्टी और रुपये का कारोबार देश के बाहर होता है? इसलिए क्योंकि भारत में वित्तीय नियमन को लेकर तमाम अवधारणाएं और गतिविधियां हैं, ऐसे कराधान और पूंजीगत नियंत्रण हैं जो निजी व्यक्तियों पर लागत का बोझ और नियामकीय तथा नीतिगत जोखिम थोपते हैं। इसे बदलने के लिए हमें देश में वित्तीय नियमन, कराधान और पूंजीगत नियंत्रण में बुनियादी बदलाव लाने होंगे। जैसा कि बजट में कहा गया, इन उत्पादों के गिफ्ट में कारोबार की इजाजत देना हल नहीं है।

इसी प्रकार कारोबारी गतिरोधों की समस्या पर विचार कीजिए। बजट भाषण में कुछ उत्पादों में ऐसे गतिरोध बढ़ाने और कुछ में घटाने की घोषणा की गई। यहां भी रणनीतिक सोच की कमी नजर आई। व्यापारिक गतिरोध उत्पादकता और निर्यात के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए खराब हैं। व्यापार नीति को लेकर न तो रणनीतिक स्तर पर कोई बड़ी सोच सामने आई, न ही विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार गतिरोध समाप्त करने की दिशा में निरंतर कदम उठाए गए।

मुझे सन 2000 के दशक के आरंभ की एक विरोधाभासी बात याद आती है जब विजय केलकर और राकेश मोहन ने कहा था कि हर बार जब टैरिफ में कटौती की जाती है तो हमारे निर्यात में इजाफा होता है। टैरिफ में कमी के उस दौर ने ही सन 2003 और उसके बाद निर्यात वृद्धि के दौर की पृष्ठभूमि तैयार की।

इस इलेक्ट्रॉनिक युग में बजट भाषण सुनने वालों की कमी नहीं है। ऐसे में भाषण लिखने वालों को राजनीतिक और आर्थिक नीति के वक्तव्य में संतुलन कायम करना पड़ता है। यह सही है कि राजनीतिक संदेश को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता लेकिन ऐसा लगता है कि मजबूत आर्थिक नीति की प्रस्तुति और क्रियान्वयन के साथ भी ऐसा किया जा सकता है।

देश में और विदेशों में भी निजी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रांति से पूरी तरह प्रभावित हैं। वे बजट भाषण में लिखी और कही गई बातों को पहले की तुलना में कहीं अधिक आसानी से ग्रहण करते हैं। जहां तक बात दृश्यता की है तो मानक अब पहले से कहीं अधिक ऊंचे हैं। अब हमें ओबामा के भाषण की गुणवत्ता से मुकाबला करना है। इस दृश्य का चित्रण करके देखें तो हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है कि कैसे एक निजी व्यक्ति (भारतीय या विदेशी) जिसने सन 2011 के बाद भारत में निवेश करना बंद कर दिया, वह इस बजट भाषण पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? क्या उसे लगेगा कि उसकी चिंताओं के बारे में सोचा जा रहा है, अब विफलताओं की वजह समझी जा चुकी है और उसका हल तलाशा गया है? शायद बजट भाषण अधिक बेहतर होता यदि उसमें 4,000 शब्दों का राजनीतिक संदेश होता और इतने ही शब्द देश और विदेश के लोगों के लिए आर्थिक रणनीति के उल्लेख में खर्च किए जाते।

निराश करने वाले इस बजट में 'करो या मरो' जैसी बात नहीं

नितिन देसाई

जुलाई 2019 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष का बजट पेश किया था, तब मैंने कहा था कि राजस्व अनुमान हकीकत से दूर हैं और वास्तविक घाटा बजट में उल्लिखित 3.3 फीसदी के बजाय 4 फीसदी के आसपास रहेगा। वित्त मंत्री ने ताजा बजट में घाटे के 3.8 फीसदी रहने की बात स्वीकार की है जिससे मेरी आशंका की पुष्टि हुई।

वर्ष 2019-20 में कर राजस्व के 18.50 लाख करोड़ रुपये रहने की बात कही गई जो 19.63 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 5.6 फीसदी कम है। वित्त मंत्री ने सन 2019-20 के व्यय के आंकड़ों के 26.99 लाख करोड़ रुपये रहने की बात कही। यदि 27.86 लाख करोड़ रुपये के बजट अनुमान से तुलना की जाए तो यह करीब 3.1 फीसदी कम है। वास्तविक नतीजे और खराब हो सकते हैं क्योंकि मौजूदा अनुमान वर्ष के अंतिम दो महीनों के कर संग्रह के अंदाजे पर निर्भर हैं। सरकार के पास हमेशा तथ्यों को छिपाने का विकल्प रहता है। वह भुगतान को लंबित करके तथा उसे भारतीय खाद्य निगम जैसे संस्थानों पर टाल कर ऐसा कर सकती है। यदि आप बजट के व्यय विवरण में वक्तव्य क्रमांक 27 को देखें तो आप पाएंगे कि अतिरिक्त बजट और अन्य संसाधन जिन्हें बजट आवंटन के लिए प्रयोग किया गया, वे सन 2017-18 के 88,000 करोड़ रुपये से बढ़कर सन 2018-19 में 1.62 लाख करोड़ रुपये, सन 2019-20 में 1.73 लाख करोड़ रुपये हो गया और 2020-21 में इसके 1.86 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। आगे आने वाले वर्ष की बात करें तो बजट में कर राजस्व में 9 फीसदी इजाफे का अनुमान जताया गया है। नॉमिनल जीडीपी में 10 फीसदी की वृद्धि के अनुमान के साथ इसमें कर लचीलापन एक के स्तर पर रहेगा। यदि 2019-20 के राजस्व के बुनियादी आंकड़े बजट में जताए अनुमान से कम निकलते हैं तो फिर यह लचीलापन कहीं अधिक होगा। मिसाल के तौर पर 2017-18 में समाप्त दशक में औसत कर लचीलापन 0.8 रहा।

सन 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में बाजार उधारी में अनुमानित वृद्धि का आंकड़ा 4 फीसदी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य पूंजीगत प्राप्तियों में भारी इजाफा हुआ है। खासतौर पर परिसंपत्तियों की बिक्री से 65,000 करोड़ से 2.1 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई। चूंकि इसका प्रभाव निजी पूंजी पर भी पड़ेगा तो ऐसे में पूंजी बाजार से सरकार की मांग 21 फीसदी तक बढ़ेगी। इसके परिणामस्वरूप 2019-20 में पूंजीगत प्राप्ति में भारी कमी का अनुमान है। बजट में अनुमानित 1.05 लाख करोड़ रुपये की तुलना में यह केवल 65,000 करोड़ रुपये रह सकता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि बजट की वृहद आर्थिक स्थिति पर करीबी दृष्टि डालनी होगी। हो सकता है कि बजट के मोर्चे पर हमें इस बार भी उन्हीं गड़बड़ियों का सामना करना पड़े जो हमने इस वर्ष अनुभव कीं। नीतिगत नवाचार की बात करें तो मध्य वर्ग के कुछ करदाताओं को छोड़कर यह बजट सबको निराश करने वाला है। मध्य वर्ग का एक तबका और कुछ विदेशी निवेशक कर दरों में राहत से प्रसन्न हो सकते हैं। वृद्धि को गति प्रदान करने की बात करें तो बुनियादी ढांचों को वित्तीय मदद मुहैया कराने के महत्त्वाकांक्षी प्रावधान और बॉन्ड बाजार को गहराई प्रदान करने की बात से लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था को मदद मिल सकती है। व्यापार उदारीकरण के बजाय सीमा शुल्क बढ़ोतरी के जरिये घरेलू विनिर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने जैसे कदम से कुछ लोग प्रसन्न होंगे लेकिन लंबी अवधि में यह नुकसानदेह साबित होगा क्योंकि इससे देश के उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का लक्ष्य दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत आय कर में छूट और रियायतों को तार्किक बनाना सही कदम है।

बजट में कुछ अन्य उपयोगी प्रावधान हैं। मसलन कर अधिकारियों तथा कंपनी कानून प्रशासन द्वारा होने वाली प्रताड़ना को कम करना। आशा की जानी चाहिए कि प्रस्तावित करदाता चार्टर ऐसा होगा जो वित्त मंत्री द्वारा अभिव्यक्त बातों पर खरा उतरे। करदाताओं के लिए चीजों को आसान करने के अन्य उपाय किए गए हैं। उदाहरण के लिए अनिवार्य अंकेक्षण की सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना और इंप्लॉयी स्टॉक ओनरशिप प्लान (ईएसओपी) धारकों को कर दायित्व के समय के चुनाव में विकल्प प्रदान करना। व्यय के मोर्चे पर देखें तो हर वर्ष बजट के भाग एक में विकास संबंधी पहलों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की जाती है। इस वर्ष बजट भाषण के भाग एक में लोकलुभावन और वोट दिलाऊ विचारों को विस्तार से समझाया गया लेकिन निवेश बढ़ाने संबंधी उपायों को सरसरी तौर पर निपटाया गया।

इस बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं बताया गया कि जब इन नई पहलों को पेश किया जाएगा तो वे किन्हें प्रतिस्थापित करेंगी और किस प्रकार नीतिगत ढांचे में समाहित होंगी। उदाहरण के लिए हर जिले को निर्यात का केंद्र बनाने की बात करें तो विनिमय दर, कर रिफंड प्रक्रिया में गतिरोध और खराब लॉजिस्टिक्स व्यवस्था के बीच यह कैसे होगा? इतना ही नहीं हर जिले को निर्यात केंद्र बनाने का लक्ष्य तय करते समय संकुलन की अर्थव्यवस्था अहम है। ऐसे में निर्यातकों के लिए भौगोलिक निकटता एक अहम पहलू है क्योंकि वे हमेशा लागत के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा के लिए जूझते रहते हैं। हर जिले को निर्यात केंद्र बनाने की बात लोकलुभावन नारा है। ध्यान रहे यह सरकार आर्थिक नीति के मोर्चे पर ऐसा ही करती आई है। हमें ऐसी नीति की जरूरत है जो निर्यात बढ़ाए। यह नीति ऐसी होनी चाहिए जो निर्यात मुनाफे को प्रभावित करने वाली बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करे। निवेशक और बाजार इस बजट से ज्यादा बेहतरी की अपेक्षा कर रहे थे। इस बजट में 'करो या मरो' जैसी कोई बात नहीं नजर आती। सरकार यहां बस कुछ करती हुई नजर आ रही है। भले ही वह जो कर रही है वह कभी पूरी तरह सामने न आए।

अप्रत्यक्ष करों में मामूली बदलाव, अधिक की थी गुंजाइश

सुकुमार मुखोपाध्याय

इस बजट में कर प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष करों के खाते में गया है। वहीं अप्रत्यक्ष करों के मोर्चे पर बहुत कम कदम उठाए गए हैं। यह एक तरह से सही भी है क्योंकि अप्रत्यक्ष कर में सीमा शुल्क और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ही आते हैं। जहां तक जीएसटी का सवाल है तो इसके कर दरों पर निर्णय बजट की परिधि के बाहर है। हालांकि इस बारे में नीतिगत चर्चा की जा सकती है और ऐसा किया भी गया है। जहां तक सीमा शुल्क का सवाल है तो उसमें अधिक बदलाव नहीं किए गए हैं। इससे वित्त मंत्री की सीमा शुल्क दरों में स्थिरता दिखाने की मंशा जाहिर होती है।

अगर जीएसटी की बात करें तो वित्त मंत्री ने कुछ ऐसी सामान्य टिप्पणियां की हैं जो नीतिगत लिहाज से अहम हैं। उन्होंने कहा है कि जीएसटी देश में किया गया सबसे ऐतिहासिक कर सुधार है। हालांकि इसमें हालात के हिसाब से लगातार बदलाव करने की जरूरत होती है। एक सरलीकृत जीएसटी रिटर्न व्यवस्था 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगी जिसे प्रायोगिक स्तर पर चलाया जा रहा है। इससे एसएमएस-आधारित फाइलिंग, रिटर्न-पूर्व फाइलिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रवाह में सुधार जैसी खासियत के चलते कारोबारियों के लिए रिटर्न फाइल कर पाना अधिक आसान हो सकेगा। रिफंड प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और इसे बिना किसी मानव संपर्क के पूरी तरह स्वचालित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस (रसीद) एक और नवाचार है जहां महत्त्वपूर्ण सूचना एक केंद्रीकृत प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रखी जाएगी और इसका इस्तेमाल जमा किए गए रिटर्न के सत्यापन एवं इनपुट क्रेडिट प्रणाली की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। आधार क्रमांक की मदद से करदाताओं का सत्यापन इस बजट में उठाया जाने वाला एक बेहद अहम कदम है। इससे नकली या वजूद न रखने वाली इकाइयों को आर्थिक प्रणाली से बाहर करने में मदद मिलेगी। मेरा मत है कि यह कर-वंचना को रोकने की दिशा में उठाया गया बेहद अहम कदम है जिसे दो साल तक इंतजार करने के बजाय पहले ही लागू कर देना चाहिए था। वित्त मंत्री ने इस बजट में सघन डेटा विश्लेषण और कृत्रिम

बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित उपकरणों के इस्तेमाल की भी घोषणा की है। इसका इस्तेमाल जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट एवं रिफंड से जुड़ी धोखाधड़ी पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। यह बेहद शानदार विचार है और सौ फीसदी बिलों के मिलान से कहीं बेहतर है। वित्त मंत्री ने बजट में इसका भी स्पष्ट उल्लेख कर बढ़िया काम किया है कि जहां भी रसीदों और इनपुट क्रेडिट कर के बीच 10 फीसदी से अधिक असमानता पाई गई है वहां इनका मिलान किया जा रहा है। वैसे इस कदम को पूरी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि 10 फीसदी बेमेल होने की भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। एक फीसदी रसीदों के मिलान में भी गड़बड़ी मिलने पर इन कंपनियों के सारे बिलों एवं रसीदों का मिलान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने भारी कर वंचना के आरोप पर स्थिति साफ कर अच्छा ही किया है। बजट में उनका यह बयान साफ करता है कि सौ फीसदी रसीदों के मिलान की कोई जरूरत नहीं है। इसे उन आलोचकों को दिया हुआ जवाब माना जा सकता है जो जीएसटी प्रणाली में एक संरचनात्मक समस्या मानकर चलते हैं। वित्त मंत्री का बयान साफ तौर पर यह बताता है कि जीएसटी व्यवस्था में कोई संरचनात्मक खामी नहीं है और बदलते हालात के हिसाब से इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मैं इस राय से पूरी तरह सहमत हूं।

जहां तक सीमा शुल्क का सवाल है तो कर दरों में किए गए बदलाव उचित ही हैं। ऐसा देखा गया है कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के चलते आयात बढ़ रहा है जिससे घरेलू उद्योगों को खतरा पैदा होने लगा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए हैं। आयात बढ़ने से घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान होने पर लागू किए गए शुल्क के संदर्भ में किए गए प्रावधान को सशक्त करने की बात भी है। कुछ उत्पादों के संदर्भ में डंपिंग-रोधी प्रावधान भी किए जा रहे हैं। प्यूरिफाइड टैरेफ्थलिक एसिड (पीटीए) पर लगा डंपिंग-रोधी शुल्क खत्म कर दिया गया है। कई रियायतें वापस ले ली गई हैं और बाकी रियायतों के बारे में सितंबर 2020 तक समग्र रूप से समीक्षा करने की बात कही गई है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि पहले की तरह यह कदम बजट के साथ ही क्यों नहीं उठाया जा सकता था? इन रियायतों को वापस लेने के बारे में सार्वजनिक स्तर पर सलाह मांगने की भी बात कही गई है। यह बात समझ में नहीं आती है। कोई भी रियायत अमूमन कुछ विनिर्माताओं या निर्यातकों या आयातकों को प्रभावित करती है और बजट निर्माण के पहले उनसे हमेशा चर्चा की जाती है। यानी जो काम बजट के समय किया जा सकता था उसे आगे के लिए टाल दिया गया है।

वित्त मंत्री ने चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण पर भी खास ध्यान दिया है। हम अब न केवल चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में उनका निर्यात भी कर रहे हैं। इस क्षेत्र को अधिक मजबूती देने के लिए बजट में मेडिकल उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क के तौर पर नाममात्र का एक स्वास्थ्य उपकर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस उपकर से मिली राशि का इस्तेमाल देश के आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा तैयार करने में होगा। यह शुल्क जुटाने का सबसे बोझिल तरीका है। इसकी जगह खुद शुल्क को ही बढ़ाया जा सकता था। एक बार उपकर का जिक्र आते ही यह आखिरकार उपकर पूल का हिस्सा हो जाएगा।

जहां शुल्क रियायतें साल भर में कभी भी हटाई जा सकती हैं, वहीं शुल्क की दरें बजट के सिवाय कभी भी बदली नहीं जा सकती हैं। सीमा शुल्क की दरों पर एक नजर डालते हैं। ये दरें 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 100, 105 और 150 फीसदी हैं। वित्त मंत्री को इन शुल्क दरों को समायोजित करते हुए कुछ चुनिंदा दरें बनानी चाहिए थीं। इसके अलावा शुल्क रियायतों से संबंधित कई तरह की सूची एवं परिस्थितियां हैं और उन्हीं अध्यायों में शुल्क की भी कई दरों का जिक्र है। अगर वित्त मंत्री ने सीमा शुल्क पर गौर किया है तो वह इस बात से इत्तफाक रखेंगी कि इन दरों को सरल बनाने के लिए बड़े सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के साथ मिलकर इस सुधार का खाका तैयार करने को कहा जा सकता है। एनआईपीएफपी अतीत में भी कई अच्छे सुझाव दे चुका है।

मेरा बजट

प्रसाद बिडप्पा
फैशन गुरु

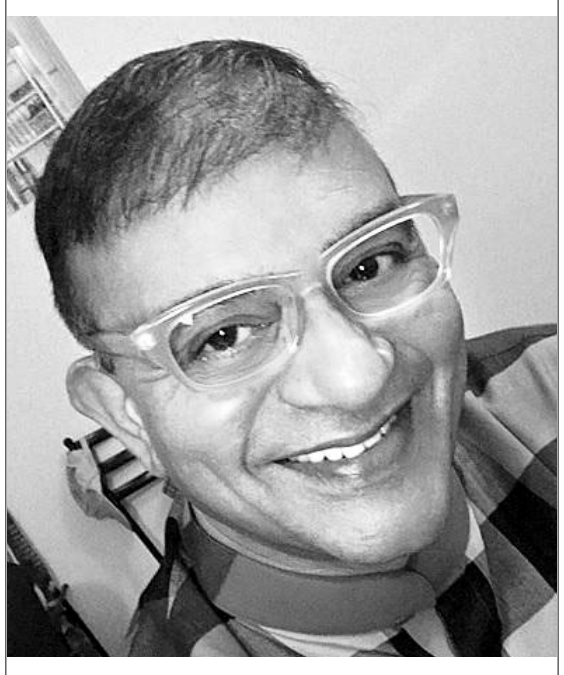

क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को संकट से बाहर निकाल लिया है?

यह कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि हमारी अर्थवव्यवस्था की मजबूती के लिए हरसंभव कदम उठाने के जरूरत है। आयकर में कमी मध्य वर्ग के लिए सकारात्मक संकेत है।

क्या यह लोकलुभावन बजट है?

इस बजट से खास तौर से किसानों को मदद मिलेगी क्योंकि कृषि क्षेत्र को खासा प्रोत्साहन दिया गया है, जिसकी काफी जरूरत थी। लेकिन ग्रामीण इलाके में अधिकतम संकट के समय खर्च में कटौती चिंताजनत है क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट आवंटन में कमी की गई है।

क्या इससे अर्थव्यवस्था को नौकरियों के सृजन और अटकी परियोजनाओं को दोबारा शुरु करने में मदद मिलेगी?

प्रधानमंत्री के कौशल विकास कार्यक्रम को भारत के कपड़ा व शिल्प क्षेत्र के पारंपरिक कौशल पर नजर डालना चाहिए ताकि युवाओं को इन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इससे काफी अंतर आएगा क्योंकि ग्रामीण इलाके में यह रोजगार का सृजन करेगा। सार्वजनिक खर्च में मजबूती से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है और कारोबार को सुरक्षा हासिल हो सकती है।

बजट प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख योजना मनरेगा के आवंटन में 2020-21 में 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 13 प्रतिशत की कमी की गई है

"इस बार के बजट में बुनियादी संरचना के विकास तथा एमएसएमई और रोजगार सृजन जैसे पक्षों पर भी ध्यान दिया गया है।"

कल्याण कृष्णमूर्ति, सीईओ, फ्लिपकार्ट

ग्रामीण आमदनी बढ़ना मुश्किल

कृषि क्षेत्र/ग्रामीण खपत

ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख योजना मनरेगा के आवंटन में 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 13 फीसदी की कमी की गई

भारत के ग्रामीण इलाकों में खपत में वृद्धि घटी है, जिससे यह उम्मीद की जा रही थी कि 2020-21 के बजट में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के हाथ में धन पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।

लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार की दो प्रमुख योजनाओं पीएम-किसान और मनरेगा के आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी करने में असफल रही हैं, जिससे ग्रामीण आमदनी को सीधे बढ़ावा मिल सकता था। हालांकि उन्होंने ग्रामीण इलाकों में भंडारण संबंधी बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए कदमों की घोषणा की है, लेकिन इसे लागू करने में लंबा वक्त लगता है। उर्वरक और खाद्य सब्सिडी में कमी करने के अलावा बजट कोई ठोस खाका खींचने में असफल रहा है।

हालांकि सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है और अब इस क्षेत्र को कॉर्पोरेट पर लागू घटी दरों के हिसाब से ही कर देना होगा। इससे किसान केंद्रित सहकारी संगठनों जैसे अमूल और चीनी सहकारी समितियों को बढ़ावा मिल सकता है।

ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख योजना मनरेगा के आवंटन में 2020-21 में 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में करीब 13 प्रतिशत की कमी की गई है। इसमें 2018-19 के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमानों में करीब 11,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई थी।

पीएम-किसान का आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 में भी 75,000 करोड़ रुपये बरकरार रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में आमदनी का समर्थन दिया जाता है। बजट दस्तावेजों से पता चलता है कि 2019-20 में आवंटित राशि 75,000 करोड़ रुपये की तुलना में संशोधित अनुमान के मुताबिक सिर्फ 54,370 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 2018-19 में जब यह योजना पहली बार पेश की गई थी तो इस मद में 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ था और इसमें से भी महज 1,241 करोड़ रुपये खर्च हो पाए थे। पहले दो वर्षों में पीएम किसान में कम खर्च की एक वजह यह हो सकती है कि किसानों के पंजीकरण में हर चरण में गिरावट आई है। पीएम-किसान की वेबसाइट के मुताबिक अब तक इस योजना में करीब 9.5 करोड़ किसानों का पंजीकरण हुआ है, जबकि 2015-16 की कृषि जनगणना के मुताबिक यह संख्या 14.5 करोड़ है।

2020-21 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 15,00,000 करोड़ रुपये तय किया गया है, जो 2019-20 के 12,00,000 करोड़ रुपये आवंटन से ज्यादा है।

सब्सिडी के माध्यम से छूट, कम अवधि के कृषि ऋण के मद में 2020-21 का बजट आवंटन 21,175 करोड़ रुपये है, जो 2019-20 के संशोधित अनुमान की तुलना में 18.54 प्रतिशत ज्यादा है।

सरकार ने बजट में यह प्रावधान ऐसे वक्त में किया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक के एक आंतरिक कार्यसमूह ने एक महीने पहले ही दिखाया था कि बहुत ज्यादा सब्सिडी वाले कृषि ऋण का इस्तेमाल कुछ राज्यों में अपात्र किसान कर रहे हैं और कृषि क्षेत्र में कर्ज उसके कृषि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में ज्यादा था।

ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा तैयार करने वाली तीन बड़ी योजनाओं पीएम आवास योजना (ग्रामीण), पीएम- ग्राम सड़क योजना और आजीविका मिशन में आवंटन 2019-20 के स्तर पर बरकरार रखा गया है और पहले दो के लिए 19,000 करोड़ रुपये और तीसरे के लिए 9,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने के लिए बजट में महज 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। कृषि सुधार पर मॉडल एक्ट को स्वीकार कर इसे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों से जोड़ने से राज्यों को इसे स्वीकार करने को प्रोत्साहन मिल सकता है। सीतारमण ने 20 लाख किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए पीएम-कुसुम के विस्तार की घोषणा की है और साथ ही 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप दिए जाएंगे। बहरहाल सरकार ने इस मद में महज 1000 करोड़ रुपये आवंटित किया है।

2020-21 के लिए कृषि ऋण का लक्ष्य 15,00,000 करोड़ रुपये तय किया गया है

किसान आय

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार की दो प्रमुख योजनाओं पीएम-किसान और मनरेगा के आवंटन में बड़ी बढ़ोतरी करने में असफल रही हैं
- पीएम-किसान का आवंटन वित्त वर्ष 2020-21 में भी 75,000 करोड़ रुपये बरकरार रखा गया है
- सब्सिडी के माध्यम से छूट, कम अवधि के कृषि ऋण के मद में बजट आवंटन 21,175 करोड़ रुपये है
- सीतारमण ने पीएम-कुसुम के विस्तार की घोषणा की

एफडीआई, ईसीबी से शिक्षा में शोध का ढांचा हो सकता है मजबूत

शिक्षा

वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) के जरिये शिक्षा में फंडिंग के वित्त मंत्री के ऐलान से इस क्षेत्र के विभिन्न संस्थानों में शोध का बुनियादी ढांचा मजबूत बन सकता है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट भाषण में कहा, 'यह महसूस किया गया कि प्रतिभावान शिक्षकों को आकर्षित करने, नवोन्मेष और बेहतर प्रयोगशाला के निर्माण की खातिर हमारी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर वित्त की दरकार है। इसलिए वाह्य वाणिज्यिक उधारी और एफडीआई हासिल करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ताकि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जा सके।' उन्होंने 2020-21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए करीब 99,300 करोड़ रुपये और कौशल विकास के लिए करीब 3,000 करोड़ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है।

शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्त मंत्री की अन्य प्रमुख घोषणाओं में जल्द ही एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने और डिग्री स्तर की पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव शामिल हैं।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'उच्च शिक्षा तक पहुंच न रखने वाले समाज के वंचित तबकों के छात्रों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डिग्री स्तर पर पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। यह केवल उन्हीं संस्थानों द्वारा मुहैया कराई जाएगी जिन्हें राष्ट्रीय संस्थानिक रैंकिंग ढांचे में शीर्ष 100 पायदान के दायरे में रैंकिंग दी गई है। शुरू में ऐसे कुछ ही संस्थानों को इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा जाएगा। भारत को उच्च शिक्षा के लिए पसंदीदा जगह बनना चाहिए। इसलिए भारत में पढ़ो कार्यक्रम के तहत इंड-सैट को एशियाई और अफ्रीकी देशों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसका इस्तेमाल उन विदेशी उम्मीदवारों के बेंचमार्किंग में किया जाएगा जो भारतीय उच्च शिक्षा केंद्रों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं।'

अधिकतर जानकारों का मानना है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट में की गई घोषणाएं उम्मीदों को कुछ हद तक पूरा करती हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि ईसीबी और एफडीआई संबंधी पहल से कहीं अधिक विदेशी पूंजी निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त होगा जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए वित्त पोषण संबंधी समस्याएं दूर होंगी।

एसवीकेएम की डीम्ड विश्वविद्यालय एनएमआईएमएस के कुलपति राजन सक्सेना ने कहा कि उच्च शिक्षा में एफडीआई की अनुमति 2016 में दी गई थी लेकिन कुछ शर्तों के कारण विदेशी निवेश आकर्षित नहीं हो सका। उन्होंने कहा, 'हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक संबंधित मंत्रालय- मानव संसाधन, वित्त एवं वाणिज्यि- इसके लिए नियम तैयार नहीं कर लेते हैं। मुझे लगता है कि जल्द घोषणा होने वाली नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा बुनियादी ढांचा, नियम-कायदे और वित्तीय व्यय में उल्लेखनीय बदलाव होगा।'

उद्योग संगठन फिक्की की सहायक महासचिव और शिक्षा सलाहकार शोभा घोष ने कहा कि ईसीबी और एफडीआई की घोषणा से इस क्षेत्र में निवेश संबंधी खाई को पाटने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के संस्थानों को अनुसंधान, छात्रवृत्ति एवं बुनियादी ढांचा विकास के लिए एक वैकल्पिक फंड उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा, 'हरेक विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र विकसित करने और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।'

शहानी ग्रुप के प्रबंध निदेशक अखिल शहानी का मानना है कि इस पहल से ट्रस्टों को ईसीबी एवं एफडीआई के जरिये रकम जुटाने में मदद मिलेगी जिससे विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) को आसान बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, 'इससे शिक्षा में विदेशी निवेश का आधार व्यापक होगा। साथ ही ईसीबी के लिए एफसीआरए जरूरतों को आसान बनाने की आवश्यकता होगी। विदेशी निवेश की सख्त जरूरत है क्योंकि शिक्षा में काफी निवेश की आवश्यकता है। विदेशी ऋण सस्ती ब्याज दरों और आसान शर्तों पर मिल सकता है।'

आईआईएम कोझिकोड के निदेशक देवाशिष चटर्जी ने कहा कि भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) इसे लेकर चिंतित नहीं है क्योंकि इस नीति का पूरा ब्यौरा मिलना अभी बाकी है। उन्होंने कहा, 'हमें इस नीति के विस्तृत ब्यौरे का इंतजार करने की जरूरत है ताकि यह पता चल सके कि क्या इसका तात्पर्य भारत में वैश्विक स्कूलों और कॉलेजों के खुलने से तो नहीं है।'

मुश्किल हालात ने बांधे सरकार के हाथ

पृष्ठ 1 का शेष

सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के लिए भी बजट में खास खबर नहीं रही। वित्त मंत्री ने वायदा किया कि 5 करोड़ रुपये तक सालाना कारोबार वाले एमएसएमई का स्वत: ऑडिट नहीं होगा और उन्हें बैंकों से सरकारी गारंटी वाला कर्ज मिलेगा। सीतारमण ने घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने वाले उपायों का सिलसिला बजट में भी जारी रखा और कुछ उत्पादों पर शुल्क बढ़ाए। डंपिंग और बढ़ता आयात रोकने की व्यवस्था को मजबूत किया गया। फर्नीचर, घरेलू वस्तुओं और उपकरणों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों पर शुल्क बढ़ाया गया और कुछ पर तो उसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी तक कर दिया गया। मगर स्क्रीन और फिंगरप्रिंट रीडर जैसे पुर्जों पर शुल्क बढ़ाने से भारत में असेंबल होने वाले फोन महंगे हो जाएंगे। बजट में वित्तीय क्षेत्र के लिए भी कुछ रखा गया। खुदरा निवेशक ल्द ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जरिये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकेंगे। कुछ सरकारी प्रतिभूतियां अनिवासी निवेशकों के लिए पूरी तरह खोल दी जाएंगे, जिससे सरकार को घरेलू बचत से कम उधार लेना पड़ेगा और भारतीय ऋण को विदेशी सूचकांकों में तेजी से शामिल होने में भी मदद मिलेगी। इससे वैश्विक धन भारत में तेजी से आएगा। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को कानूनी समर्थन दिए जाने का वायदा भी बजट में किया गया, जिससे कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार में गहराई आएगी। आईडीबीआई बैंक में सरकार की बची-खुची हिस्सेदारी भी बेच दी जाएगी। वित्त मंत्री ने पहले से चल रही कई योजनाओं को आगे जाकर भारी धन देने का वायदा भी किया, जिनमें जलजीवन पेयजल योजना शामिल है। सीतारमण ने कहा कि इस योजना के लिए कुल मिलाकर 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित होंगे मगर बजट में इसके लिए केवल 11,500 करोड़ रुपये ही दिए गए। बजट में खर्च में कंजूसी बरती गई। खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर सब्सिडी नए वित्त वर्ष में भी 2.3 लाख करोड़ रुपये ही रहेगी। वास्तविक जीडीपी के संदर्भ में रक्षा पर खर्च केवल 2 फीसदी बढ़ा गया। खर्च में इस तरह की कटौती से वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे की लगाम तो कस ली, लेकिन मांग में कमी जारी रहने का खटका भी इससे पैदा हो गया है।

बजट के संदेश पर पसोपेश में सांसद

राजनीतिक नजरिया

वित्त मंत्री द्वारा दिए गए लंबे भाषण के अलावा आम बजट में रखे गए कई प्रस्ताव भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों की चिंता बढ़ाते हुए दिखे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 160 मिनट लंबा बजट भाषण खत्म होने के बाद विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के सांसद भी लोकसभा से एक झुंड की तरह जल्द बाहर निकलने को आतुर दिखे। यह एक तरह से वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट के असर को दर्शा रहा था।

नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2015 में अपना बजट दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के एक पखवाड़े बाद पेश किया था और उसमें गरीबों के कल्याण को अपना केंद्रीय विषय बनाया था। उसके ठीक पांच साल बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव महज एक हफ्ते दूर होने के बीच मोदी सरकार ने मध्य वर्ग को आकर्षित करने के लिए नई आयकर दरों की घोषणा कर दी है। इस घोषणा ने जहां दिल्ली के सांसदों को खुश किया वहीं हिंदीभाषी क्षेत्रों से ताल्लुक रखने वाले सांसद इस बात को लेकर पसोपेश में दिखे कि वे अपने क्षेत्रों में बजट के बारे में क्या संदेश लेकर जाएं?

खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडी में की गई कटौतियों को लेकर सांसद चिंतित दिखे तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देने वाली मनरेगा योजना के बजट आवंटन में की गई कमी भी उनकी परेशानी का सबब बन सकती है। इस साल का बजट 2015 के बजट की ही तरह महत्त्वपूर्ण है। दोनों ही बार केंद्र में आम चुनाव के बाद पहला पूर्ण बजट पेश किया गया है। इसके अलावा इन दोनों वर्षों में केवल दो राज्यों में ही विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से यह अपेक्षित था कि वह आर्थिक सुधारों को तेज करने और नई योजनाएं लाने में अधिक साहस का परिचय देगी। लेकिन ऐसा न तो 2015 में हो पाया था और न ही इस बार ऐसा हुआ है।

अगर 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मुद्रास्फीति पर काबू पाने को अपने बजट का मुख्य बिंदु बताया था तो 2020 के बजट में सत्तारूढ़ सांसद सीतारमण से महंगाई पर काबू पाने का कोई भी भरोसा हासिल नहीं कर पाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सात फीसदी से अधिक है और खाद्य मुद्रास्फीति तो 10 फीसदी से भी ऊपर चल रही है।

बहरहाल इस बात की पूरी आशंका है कि सरकार को सार्वजनिक बीमा कंपनी एलआईसी और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश पर न केवल विपक्षी दलों बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का भी तगड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इसे हड़बड़ी में किया जाने वाला निजीकरण बताया है।

वहीं अन्य विपक्षी दलों ने एलआईसी में हिस्सा बेचने की योजना को आर्थिक सुस्ती एवं नोटबंदी का ठीकरा राज्यों पर फोड़ने की कोशिश बताया है। उनका कहना है कि वित्त मंत्री ने कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को और घटाने की बात कही है। इससे केंद्र एवं राज्यों के बीच तनातनी और बढ़ने की आशंका है।

भारतीय धरोहर एवं संरक्षण संस्थान को स्थापित करने के प्रस्ताव, संस्कृति मंत्रालय के लिए 3,150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय के लिए 2,500 करोड़ रुपये के आवंटन का भाजपा के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर बड़े उत्साह से स्वागत किया। सीतारमण ने कहा, 'संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्व विज्ञान जैसी विधाओं में ज्ञान अर्जित करना, इन निष्कर्षों के वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटाने और इनका विश्लेषण करने और और उच्च स्तरीय संग्रहालयों के माध्यम से इनका प्रचार-प्रसार करना जरूरी है।'

वित्त मंत्री ने झारखंड राज्य की राजधानी रांची में एक जनजातीय संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, 'पांच पुरातत्व स्थलों हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु में स्थानिक संग्रहालय बनाया जाएगा।' इनमें से ज्यादातर भाजपा शासित राज्य हैं जबकि तमिलनाडु में इसके सहयोगी दल अन्नाद्रमुक की सरकार है।

वित्त मंत्री ने एक रोचक दावा किया कि सिंधु सभ्यता की पांडुलिपियों का गूढ़ अर्थ स्पष्ट कर लिया गया है। वाणिज्य और व्यापार संबंधी शब्दों से पता चलता है कि कैसे भारत सैकड़ों सालों से कौशल, धातु कर्म, व्यापार आदि में समृद्ध रहा है।' हालांकि बजट में रोजगार सृजन पर कुछ खास नहीं था, ऐसे में विपक्ष ने सवाल किया, 'मौजूदा वृद्धि दर के साथ 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाएगा?'

फोटोः पीटीआई

शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करने के लिए संसद पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

चुनावी रणनीति के लिए बजट!

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल (2014 से 2019) में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया था जिसमें बजट पेश करने की तारीख में बदलाव जैसे कदम भी शामिल हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले ही बजट पेश करने की तारीख 28 फरवरी के बजाय 1 फरवरी तय कर दी गई। इस साल भी दो राज्यों में चुनाव होने हैं। दिल्ली में 8 फरवरी जबकि बिहार में अक्टूबर में चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री ने नए आयकर स्लैब की घोषणा दिल्ली के मतदाताओं को लुभाने के लिए की।

वित्त मंत्री ने सरकार की विनिवेश पहल के तहत एलआईसी को बाजार में सूचीबद्ध करने का जो प्रस्ताव रखा है उसे विपक्ष के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। लगभग सभी विपक्षी दलों ने कहा कि वे इस योजना का विरोध करेंगे। एलआईसी के कर्मचारी संगठनों ने कहा कि सरकार का यह कदम 'राष्ट्रीय हित के खिलाफ' है और इससे 'देश की आर्थिक संप्रभुता खतरे में' पड़ जाएगी। संगठनों ने कहा कि एलआईसी के कर्मचारी संगठन विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकारी उपक्रमों के विनिवेश का विरोध किया है।

सीतारमण ने पिता से आशीर्वाद के बाद शुरू किया भाषण

संसद की झलकियां

वित्त मंत्री ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत बुलंद आवाज के साथ की लेकिन ऐतिहासिक रूप से लंबा बजट भाषण देते हुए उनकी तबीयत खराब हो गई और वह अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ सकीं

शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट की शानदार शुरुआत हुई। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन की दर्शक दीर्घा में बैठे अपने पिता को बड़ी फुर्ती से नमस्कार करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। जब सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तब उनकी आवाज काफी बुलंद थी और उसमें कहीं कोई चूक या घबराहट नहीं नजर नहीं आ रही थी। सदन में बैठे सभी लोग और दर्शक दीर्घा में मौजूद उनकी बेटी पी वांग्मयी सहित उनके परिवार के चार सदस्य अपनी सीट पर जमे थे। उस वक्त दिन के करीब 11 बजे थे। साल के दूसरे सबसे बहुप्रतीक्षित भाषण का सबको इंतजार था। पहला भाषण स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया जाने वाला संबोधन माना जाता है जिसका देश भर में सबको इंतजार होता है।

लेकिन दिन के 12 बजकर 39 मिनट हुए तो आगरा की सांसद और अभिनेत्री हेमामालिनी की आंखें बंद होने लगीं जब वित्त मंत्री ने कर प्रस्तावों का ब्योरा देना शुरू कर दिया। ये ब्योरे पढ़ने के साथ ही बीच-बीच में पानी की घूंट से अपना गला भी तर कर रही थीं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे बैठकर अपना भाषण जारी रखने का आग्रह किया। साफतौर पर दिख रहा था कि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थीं। दर्शक दीर्घा में बैठी उनकी बेटी वांग्मयी ने अपने होंठ को दांतों से दबाये रखा था। लेकिन सीतारमण ने अपना हौसला बुलंद रखते हुए उन पंक्तियों को दोहराना जारी रखा जिसे वे बेहद जरूरी मान रही थीं। हालांकि विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने उनसे यह गुजारिश की कि सभी उनकी बातों को सुन पा रहे हैं इसलिए उसे दोहराने की जरूरत नहीं है।

कुछ मिनट बाद ही सीतारमण बैठते हुए बुदबुदाने लगीं कि बाकी के बजट को पढ़ा हुआ ही माना जाए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कुछ लोगों ने उन्हें होम्योपैथिक टैबलेट देने की कोशिश की जबकि कुछ सांसद उन्हें सीट पर ही बैठे रहने की सलाह दे रहे थे। कुछ लोगों ने उनका हाथ पकड़ कर अच्छे सेहत की कामना की जबकि भीड़ छंटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बजट पेश करने के लिए बधाई दी। हालांकि विपक्षी दलों और राजग के उनके शुभचिंतकों ने ही बधाई दी। सीतारमण की तबीयत में तब तक कुछ सुधार सा दिखा और उन्होंने हाथ हिलाकर अपने परिवार को आश्वस्त किया। हालांकि उनकी बेटी तब तक बाहर निकल चुकी थीं और वह वित्त मंत्री के कमरे तक जाने का इंतजार कर रही थीं। इस बीच एक रिपोर्टर ने कहा कि उनकी मां को लेकर वह चिंतित हैं तब वांग्मयी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, 'मुझे पूरा यकीन है कि वह ठीक हो जाएंगी।'

सीतारमण को आज चिंतित होने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि विपक्ष के अग्रणी नेता मसलन सोनिया गांधी, शरद पवार मौजूद नहीं थे और तृणमूल कांग्रेस ने कमान संभाल रखी थी। जब सीतारमण कश्मीरी कवि दीनानाथ कौल की पंक्तियां पढ़ रही थीं तब सौगत रॉय ने कहा कि सब तो जेल में हैं। हालांकि सीतारमण ने कौल का उर्दू उपनाम 'नदीम' नहीं बोला। कौल ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला की तारीफ में एक कविता लिखी थी जब उन्हें जेल से रिहा किया गया था जिसे अब भी कश्मीर में याद किया जाता है। जब वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि देश के शीर्ष 100 शैक्षणिक संस्थान एक ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम की पेशकश करेंगे तब वांग्मयी ने भी अन्य सांसदों के साथ ही उत्साह में मेज थपथपाई।

ऊर्जा मंत्री आर के सिंह तब उत्साह से भरे दिखे जब किसानों की बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी योजना की पेशकश की गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रविशंकर प्रसाद और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तब मेज थपथपाते नजर आए जब वित्त मंत्री ने देश में मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की।

गोयल रेल मंत्रालय की कमान भी संभाल रहे हैं ऐसे में जब सीतारमण ने 500 वाईफाई से लैस रेलवे स्टेशन की घोषणा की तब उन्होंने खुश होकर सिर हिलाया। निश्चित तौर पर यह संख्या काफी ज्यादा है। हालांकि विपक्ष का रोष तब देखने को मिला जब सीतारमण ने एक वाक्य में बड़ी तेजी से यह घोषणा कर दी कि सरकार जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी। बजट के बाद एक मलयाली सांसद ने कहा, 'जीवन बीमा निगम के बगैर आखिर जीवन क्या है मैडम।'

वित्त मंत्री के पिता और बेटी पी वांग्मयी सहित परिवार के चार सदस्य सदन में थे मौजूद

बजट पर बोल

"आम बजट में एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने का केंद्र सरकार का प्रस्ताव सार्वजनिक संस्थानों की विरासत पर हमला करने की योजना है। यह सुरक्षा की भावना का अंत है। क्या यह एक युग का भी अंत है?

ममता बनर्जी
मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

"यह बजट देश के बुनियादी ढांचागत विकास के साथ ही किसानों के उन्नयन, नौजवानों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

"बजट आंकड़ों का मायाजाल है और इसमें आर्थिक मंदी और महंगाई से निपटने के लिए किसी कार्ययोजना का अभाव है। इसमें गांव,गरीब, युवा, किसान, रोजगार, महिला सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं है। इसमें किसानों को खोखले सपने दिखाए गए हैं

कमलनाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

"आम बजट में इस बार भी दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। दिल्ली को बजट से बहुत उम्मीदें थीं। सवाल यह भी है कि चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को निराश कर रही है तो क्या यह विधानसभा चुनाव के बाद अपने वादे निभाएगी?

अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

"यह आम बजट महाराष्ट्र के लिए काफी निराशाजनक है। इसमें राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास को गति नहीं दी गई है, केवल पहले से घोषित मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है

उद्धव ठाकरे
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

वित्त आयोग ने कर कोष में राज्यों की हिस्सेदारी में की मामूली कटौती

बजट और वित्त आयोग

15वें वित्त आयोग ने साल 2020-21 के लिए विभाज्य कर कोष से राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी में एक प्रतिशत कटौती की सिफारिश की

पंद्रवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विभाज्य कर कोष से राज्यों को दिए जाने वाले हिस्से को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। इसका प्रमुख कारण हाल ही में गठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का बनना तथा राज्यों की कुल संख्या 29 से घटकर 28 होना है।

आयोग ने दो पैमानों में राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि देने की भी सिफारिश की है। पहला, भौगोलिक प्रदर्शन तथा दूसरा, कर संबंधी प्रयास। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले वर्षों में इन पैमानों के अलावा दूसरी मानदंडों को पूरा करने पर भी राज्यों को प्रोत्साहन राशि देने की सिफारिश की जाएगी।

15वें वित्त आयोग की अवधि 11 महीने के लिए बढ़ाई गई थी और यह साल 2020-21 से 2025-26 के लिए अपनी दूसरी रिपोर्ट अक्टूबर महीने में जमा करेगा। अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग ने कहा है कि यह कई प्रमुख सिफारिशों की विस्तृत जांच करके उन्हें दूसरी रिपोर्ट में शामिल करेगा। जैसे, अलग से रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा निधि बनाने की व्यवहार्यता, जिसके लिए आयोग सिफारिशें करने से पहले अलग से एक विशेषज्ञ समूह का गठन करेगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार को आने वाले वर्षों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अधिक युक्तिसंगत बनाना चाहिए और केंद्र तथा राज्य बजट के बाहर की अपनी उधारी को पूरी तरह से जाहिर करे। इसमें कहा गया, 'आयोग ने देखा है कि केंद्र तथा राज्य सरकारें संचित निधि के बाहर से भी उधारी लेते हैं, जिससे अतिरिक्त बजटीय देनदारियां बढ़ जाती हैं। हम सिफारिश करते हैं कि पारदर्शिता को बढ़ाते हुए केंद्र तथा राज्य, दोनों को बजट के अलावा बाहरी उधारियों का पूर्ण प्रकटीकरण करने एवं उन्हें समयबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।' 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतिम वर्ष, 2019-20 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले वित्त वर्ष 2020-21 के राजस्व घाटा अनुदान में 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में केंद्रीय बजट पेश करने के साथ ही 15वें वित्त आयोग द्वारा जमा की गई रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि वह 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों के लिए की गई 42 प्रतिशत हिस्सेदारी की सिफारिशों को बनाए रखना चाहता था लेकिन उसे नए केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के बारे में भी विचार करना पड़ा।

रिपोर्ट में कहा गया, 'हमने अपनी अनुमानों में पाया कि विभाज्य कर कोष में जम्मू कश्मीर का हिस्सा करीब 0.85 प्रतिशत होगा। हमारा मानना है कि इसे बढ़ाकर एक प्रतिशत किया जा सकता है जिससे दोनों केंद्र शासित राज्यों में सुरक्षा तथा दूसरी विशेष जरूरतों को पूरा किया जा सके।'

इसमें लिखा गया, 'चूंकि नवगठित दोनों केंद्र शासित राज्यों का यह खर्च केंद्र के हिस्से से किया जाएगा, इसलिए हम राज्यों की हिस्सेदारी एक प्रतिशत घटाकर 41 प्रतिशत करने की सिफारिश करते हैं।'

ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव कहते हैं, 'यह बदलाव मामूली तौर पर केंद्र के पक्ष में आएगा।' संसद में बजट पेश करते समय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने 15वें वित्त आयोग की 'अधिकांश' सिफारिशों को मानने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नॉमिनल जीडीपी दर 10 प्रतिशत तथा 2020-21 के लिए 11 प्रतिशत रहने के अनुमान के साथ 15वें वित्त आयोग ने काफी आशावादी अनुमान जाहिर किए हैं। आर्थिक वृद्धि के इन अनुमानों के आधार पर राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिशों को कम करने आंका गया है।'

स्थानीय निकायों पर खर्च के मामले में 15वें वित्त आयोग ने कहा, 'हम वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपये की राशि देने की सिफारिश करते हैं, जो अनुमानित विभाज्य पूल का 4.3 प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय निकाय अनुदान की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि हम शहरों को विकास के इंजन के रूप में मानते हैं।'

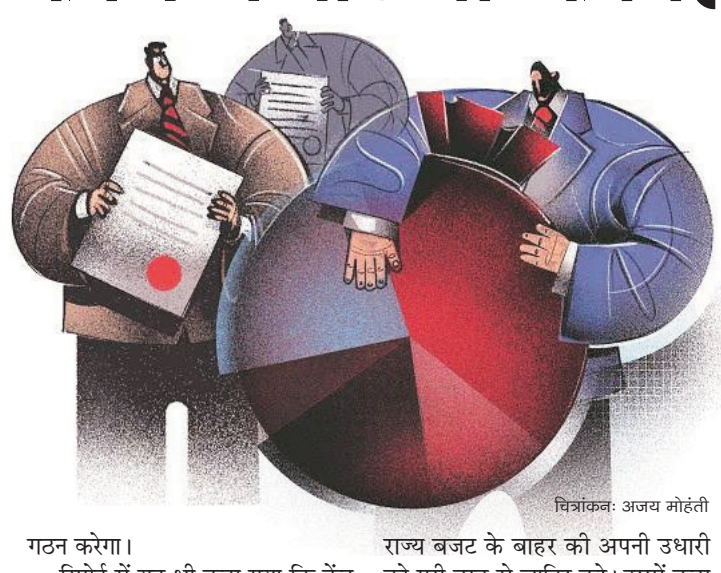

चित्रांकनः अजय मोहंती